वर्ष: 6 अंक: 18 16-31 मार्च, 2026 (निःशुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

इंडिया एआई-इंपैक्ट समिट

AI IMPACT SUMMIT भारत 2026 INDIA

एआई ग्लोबल परिदृश्य में भारत की नई पहचान

मस्तिष्कों का महासंगम इंडिया एआई इंपैक्ट समिट- 2026 बना एआई के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व की घोषणा का अवसर, जहां दुनिया को मिला एआई का 'मानव' विजन...

ई-कॉपी के लिए QR स्कैन करें

मातृभूमि की जड़ों से जुड़े रहते हैं भारतीय, कर्मभूमि के विकास में करते हैं सहयोग

'मन की बात' देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। हर महीने 'मन की बात' के लिए ढेरों सुझाव मिलते हैं। भेजे गए संदेशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के कोने-कोने में छिपी अद्भुत प्रतिभाओं की जानकारी मिलती है। निजी स्वार्थ से उठकर समाज के लिए कुछ करने की अनेक प्रेरणादायी गाथाएं मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशभर के लोगों तक पहुंचती हैं। 22 फरवरी को 'मन की बात' कार्यक्रम में एआई की उपलब्धियों से लेकर टी-20 वर्ल्ड कप तक कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर हुई बात। प्रस्तुत है प्रमुख अंश...

- **टर्निंग प्वाइंट :** कई देशों के नेता, उद्योग जगत के लीडर, इनोवेटर और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े लोग, एआई इंपैक्ट समिट के लिये भारत मंडपम में एकत्र हुए। आने वाले समय में एआई की शक्ति का उपयोग दुनिया किस प्रकार करेगी इस दिशा में यह समिट एक टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ।
- **अद्भुत क्षमताएं :** समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली। इस दौरान भारत ने तीन मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लांच किए। यह अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही, जिसको लेकर युवाओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था।
- **भारतीयों की विशेषता :** भारतीय जहां भी जाते हैं, वे अपनी मातृभूमि की जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी कर्मभूमि, यानी जिस देश में वे रहते हैं, उसके विकास में योगदान देते हैं।
- **अंगदान :** भारत में अंगदान को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे उन लोगों की मदद हो रही है, जिन्हें इसकी जरूरत है। साथ ही देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है। इस दिशा में कई संस्थाएं और लोग असाधारण कार्य कर रहे हैं।
- **अमृत महोत्सव :** आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मैंने पंच प्राणों की बात कही थी जिसमें से एक है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। आज देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़कर भारत की संस्कृति से जुड़ी चीजों को महत्व देने लगा है। इस दिशा में राष्ट्रपति भवन ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में 'राजाजी उत्सव' मनाया।
- **सतर्क रहना है :** हमें सतर्क रहना है और धोखेबाजों के झांसे में नहीं आना है। केवाईसी या रि-केवाईसी केवल अपने बैंक की शाखा या आधिकारिक एप और ऑथराइज्ड मीडियम से ही कराएं। ओटीपी, आधार नंबर या बैंक खाते संबंधी जानकारी किसी को न दें। पासवर्ड समय-समय पर जरूर बदलते रहें।
- **परंपरा और टेक्नोलॉजी :** किसान केवल अन्नदाता नहीं हैं। वे धरती के सच्चे साधक हैं। मिट्टी को सोना बनाना क्या होता है, ये कोई हमारे किसानों से सीखे। आज का किसान परंपरा और टेक्नोलॉजी, दोनों को साथ लेकर चल रहा है।
- **आस्था की धारा :** महाकुंभ हो या केरला कुंभ, यह केवल स्नान का पर्व नहीं है। यह स्मृति का जागरण है। यह संस्कृति का पुनर्स्मरण है। उत्तर से दक्षिण तक, नदियां भले अलग हों, किनारे भले अलग हों, पर आस्था की धारा एक ही है- यही भारत है।
- **लोकप्रिय लीडर :** हमारे देश में ऐसे लोग हमेशा जनता के दिलों में बसे रहते हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किया होता है। जिन्होंने अपने नेक कार्यों में जनता को प्राथमिकता दी होती है। अम्मा जयललिता जी, ऐसी ही एक लोकप्रिय लीडर थीं। ■

'मन की बात' पूरी सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

न्यू इंडिया
समाचार
वर्ष: 6, अंक: 18 | 16-31 मार्च, 2026

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

आवरण कथा

इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट 2026 में 'मानव' विजन के माध्यम से भारत ने दिखाया कि किस तरह नई तकनीक का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जा सकता है। यह वैश्विक सम्मेलन इस बात का प्रमाण बना कि भारत के पास वैश्विक एआई क्रांति का नेतृत्व करने की क्षमता भी है और सामर्थ्य भी... | 10-27

सेमीकंडक्टर यूनिट

चिप निर्माण में भारत बनेगा आत्मनिर्भर

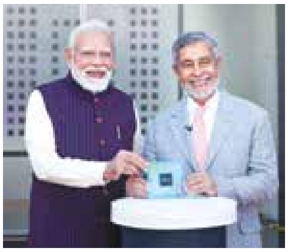

पीएम मोदी ने साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग केंद्र का किया उद्घाटन | 30-31

नमो भारत का विस्तार
सुगम यात्रा, समृद्धि अपार

पीएम मोदी ने एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का किया शुभारंभ | 34-35

समाचार सार | 4-5

व्यक्तित्व : सूर्य सेन
चटगांव विद्रोह के नायक | 6

सामर्थ्य को सशक्त करने का निरंतर प्रयास
न्यूज 18 राइजिंग भारत शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित | 7

राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस : स्वस्थ भारत की मजबूत नींव
राजस्थान से राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत | 8-9

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय : 'केरल' होगा अब 'केरलम'
सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय | 28-29

मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर... जीवन होगा और बेहतर
तमिलनाडु-पुडुचेरी को मिली 7,100 करोड़ रुपये की सौगातें | 32-33

बजट वेबिनार... बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट वेबिनार किया संबोधित | 36-37

भारत की शक्तिशाली समुद्री क्रांति
सागरमाला कार्यक्रम से पत्तन विकास और कनेक्टिविटी को मिली मजबूती | 38-39

राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव
राष्ट्रपति ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का किया अनावरण | 40-41

राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर
राजस्थान को पीएम मोदी ने दी 17,000 करोड़ रु. की विकास की सौगातें | 42

पूंजी और सामर्थ्य की संयुक्त आर्थिक शक्ति
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की चार दिवसीय भारत यात्रा | 43

रणनीतिक विश्वास से वैश्विक नेतृत्व तक
भारत-फ्रांस सहयोग का नया अध्याय | 44-45

रणनीति से नवाचार तक भारत-इजरायल संबंधों का विस्तार
पीएम नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय इजरायल यात्रा | 46-48

प्रकाशक: कंचन प्रसाद, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **पत्राचार और ईमेल के लिए पता:** कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003. **ईमेल- response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812**

संपादक की कलम से...

मानवता के लिए एआई
वैश्विक सहयोग में भारत की अग्रणी भूमिका

सादर नमस्कार।

16 से 21 फरवरी के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित "एआई इंपैक्ट समिट-2026" ने भारत को वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विमर्श के केंद्र में स्थापित कर दिया। "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" की भावना से प्रेरित इस ऐतिहासिक आयोजन में 118 देशों की भागीदारी और 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति ने इसे विश्व स्तर का सफल मंच बना दिया। पांच लाख से अधिक प्रतिभागियों, 550 से ज्यादा प्री-समिट आयोजनों, 100 से अधिक वैश्विक एआई प्रमुखों, 500 से अधिक विशेषज्ञों और 2.5 लाख विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता ने इसे दुनिया के सबसे बड़े एआई सम्मेलनों में स्थान दिलाया। जिम्मेदार और नैतिक एआई पर विद्यार्थियों की चर्चा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया।

इस समिट में भारत ने विश्व के समक्ष एआई को मानवता की सेवा के लिए उपयोगी बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। "इंडिया एआई मिशन" आमजन के हित में उत्तरदायी एआई को सुलभ बना रहा है।

समिट में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के वादे 250 अरब डॉलर से अधिक रहे, जबकि डीप-टेक वेंचर पर लगभग 20 अरब डॉलर खर्च करने के प्रति भी प्रतिबद्धताएं सामने आई। यह भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में बढ़ते वैश्विक विश्वास का प्रमाण है।

एआई इंपैक्ट समिट 2026 का समापन नई दिल्ली घोषणा के साथ हुआ, जिसमें 91 देशों और संगठनों ने सात स्तंभों पर आधारित साझा वैश्विक दृष्टि का समर्थन किया। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एआई के लिए 'मानव' विजन तथा विकास के उत्प्रेरक के रूप में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर भी बल दिया है।

विकसित भारत की यात्रा में एआई का महत्व और इस दिशा में भारत की राष्ट्रीय पहल ही इस बार के अंक की हमारी आवरण कथा बनी है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में चटगांव विद्रोह के नायक सूर्य सेन, फ्लैगशिप में सागरमाला कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर विशेष सामग्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, राष्ट्रपति भवन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा सहित उनके पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर 23 मार्च को होने वाले शहीद दिवस पर विशेष सामग्री समाहित है।

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

राष्ट्रीय डेवलपमेंट और सरकारी पहल से अपडेट रखने में बहुत महत्वपूर्ण

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका बहुत अधिक जानकारी देने वाला लगता है। यह हमारे कर्मचारियों को लेटेस्ट राष्ट्रीय डेवलपमेंट और सरकारी पहल से अपडेट रखने के लिए बहुत काम का लगता है। यह सरकार के कदमों के बारे में एक ज्ञानवर्धक पत्रिका है। मैं चाहता हूं कि नियमित रूप से यह पत्रिका मुझे मिलती रहे। ताकि मैं देश में हो रहे विकास कार्य एवं योजना से अवगत रह सकूं।

meghalayashikshasamiti02@gmail.com

योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में जानने का मंच

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका देश में चल रही केंद्र सरकार की योजना, कार्यक्रम और विकास गतिविधियों के बारे में जानकारी पाने का एक शानदार जरिया है। मैं इस पत्रिका के माध्यम से देश में हो रही विकासात्मक गतिविधियों के बारे में जान पा रहा हूं। यह एक शानदार पत्रिका है।

mhqchoutuppal@gmail.com

विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य में अतुलनीय योगदान

विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य में 'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका का योगदान अतुलनीय है। आज तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी समसामयिकी विषय के लिए अनावश्यक पुस्तकों का अध्ययन करते रहें। वर्तमान में प्रश्न पत्रों में बदलाव किया गया है। ऐसे में समसामयिकी विषय के लिए 'न्यू इंडिया समाचार' में प्रकाशित खबर काफी उपयोगी साबित हो रही है। इसलिए संपादक महोदय से निवेदन है कि बहुत ही सारगर्भित सामग्री देकर लाखों बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाते रहें।

akshubishnoiraj@gmail.com

योजनाओं की जानकारी देने में बहुत मददगार

मेरा नाम तथागत भट्टाचार्य है। मैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रहता हूं। मुझे न्यू इंडिया समाचार बहुत पसंद है। यह एक अच्छी पत्रिका है। यह मेरे लिए देश में चल रही विकासात्मक गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जानने में बहुत मददगार है।

bhattacharyyatathagata6@gmail.com

परीक्षा की तैयारी में जानकारी का भरोसेमंद साथी

मेरा नाम सौरव शर्मा है। मुझे न्यू इंडिया समाचार मैगजीन के हर एडिशन का बेसब्री से इंतजार रहता है। हर नया एडिशन उन टॉपिक को कवर करता है जो हमारे देश और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। यह मैगजीन एग्जाम की तैयारी के लिए भी भरोसेमंद जानकारी का एक बेहतरीन सोर्स है।

सौरव शर्मा

sharmasourav1261@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003, ईमेल- response-nis@pib.gov.in

राष्ट्रपति ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' में भरी उड़ान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 27 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' में उड़ान भरीं। इससे पहले राष्ट्रपति, वर्ष 2023 और 2025 में सुखोई 30 एमकेआई और राफेल में भी उड़ान भर चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ग्रुप कैप्टन नयन शांतिलाल बहुआ के साथ उड़ान भरी। लगभग 25 मिनट के इस मिशन के दौरान गडिसर झील और जैसलमेर किले के ऊपर से उड़ान भरी और एक टैंक लक्ष्य पर भी हमला किया। उड़ान के बाद अपने अनुभव में राष्ट्रपति ने कहा, "भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' में उड़ान भरना मेरे लिए एक समृद्ध अनुभव रहा है। इस उड़ान ने मुझे राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं पर नए सिरे से गर्व का अनुभव कराया है। मैं भारतीय वायु सेना और वायु सेना स्टेशन जैसलमेर की पूरी टीम को इस उड़ान के सफल आयोजन के लिए बधाई देती हूं।"

तमिलनाडु के किसानों को मिला वैश्विक मंच

कृषि निर्यात के क्षेत्र में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु से कनाडा के लिए जीआई टैग वाले पहले सलेम साबूदाने की खेप को रवाना किया गया। इस निर्यात से टैपिओका साबूदाना की खेती में लगे आदिवासी समुदाय सहित बड़ी संख्या में किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही, देश के कृषि निर्यात को मजबूती मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार के भी अवसर खुलेंगे। तमिलनाडु टैपिओका का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। सलेम का साबूदाना उद्योग टैपिओका की खेती में लगे जनजातीय समुदायों और हजारों किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है। सलेम को साबूदाना और स्टार्च के प्रमुख केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह हजारों किसान परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार भी है।

'अंजदीप'
भारत का नया योद्धा

भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक क्षमता को सशक्त बनाने की दिशा में भारत का नया योद्धा 'अंजदीप' एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आईएनएस अंजदीप पोत को 27 फरवरी को भारतीय नौसेना ने चेन्नई पोर्ट पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी की मौजूदगी में कमीशन किया। इस पोत को 'डॉल्फिन हंटर' के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और उन्हें निष्क्रिय करना है। इस पोत से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं और तटीय निगरानी को बढ़ावा मिलेगा। पोत को स्वदेशी, अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी हथियारों और सेंसर पैकेज से सुसज्जित किया गया है। इसमें हल माउंटेड सोनार अभय शामिल है। हल्के टॉरपीडो एवं पनडुब्बी रोधी रॉकेटों से भी लैस है।

सड़क दुर्घटना के घायलों को कैशलेस उपचार देने की पहल

किसी भी सड़क हादसे में घायलों को गोल्डन ऑवर में इलाज से वंचित न होना पड़े इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत (सड़क दुर्घटना अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार) योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। योजना के तहत किसी भी श्रेणी की सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से सात दिनों के लिए एक लाख 50 हजार रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि अस्पतालों को मोटर वाहन दुर्घटना कोष के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा। अध्ययन से पता चलता है कि यदि पीड़ितों को पहले घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती करा लिया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली लगभग 50 प्रतिशत मौतों को टाला जा सकता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे विकसित होंगे मधुमक्खी गलियारे

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारा विकसित करने की एक अनूठी पहल की घोषणा की है। 'मधुमक्खी गलियारे' में मधुमक्खी अनुकूल पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। यह पहल मधुमक्खियों के साथ ही ऐसे जीवों के लिए भी उपयोगी होगा जो पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं। पौधों की प्रजातियों का चयन इस प्रकार किया जाएगा जिससे पूरे वर्ष निरंतर फूल खिलने का चक्र बना रहे। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे नीम, करंज, महुआ, पलाश, बॉटल ब्रश, जामुन और सिरिस सहित देशी प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। एनएचएआई का लक्ष्य वर्ष 2026-27 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगभग 40 लाख पेड़ लगाने का है, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत वृक्ष 'मधुमक्खी गलियारा' पहल के अंतर्गत लगाए जाएंगे।

योग में है योगदान

तो करें प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र ने रिकॉर्ड देशों के समर्थन के साथ हर वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया था। उसी योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू प्रधानमंत्री योग पुरस्कार की सीरिज में 2026 के लिए उन व्यक्तियों और संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किया गया है जिनके निरंतर प्रयासों से योग का प्रभाव बढ़ा है। पुरस्कार के लिए आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in पर किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 21 मार्च 2026 है। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि आवश्यकता पड़ने पर पंजीकरण की तिथि 15 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक ट्रॉफी, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार-2026 में व्यक्तिगत और संस्था दोनों श्रेणियों में राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो-दो पुरस्कार दिए जाएंगे।

■ जन्म : 22 मार्च 1894 ■ मृत्यु : 12 जनवरी 1934

चटगांव विद्रोह के नायक

भारत की आजादी के लिए अपना खून बहाने वाले सूर्य सेन ने न सिर्फ मरते दम तक ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि कई बार उन्हें गहरी चोट भी दी। मां भारती के वीर सपूत, चटगांव विद्रोह के नायक एवं 'मास्टर दा' के नाम से पहचान रखने वाले महान क्रांतिकारी सूर्य सेन ने अंग्रेजों से लड़ने का अलग तरीका अपनाया। क्रूर अंग्रेज अधिकारियों ने सूर्य सेन को फांसी से ठीक पहले बेरहमी से प्रताड़ित किया, फिर भी नहीं तोड़ सके उनकी हिम्मत...

औपनिवेशिक काल में अविभाजित बंगाल का हिस्सा रहे चटगांव (वर्तमान बांग्लादेश में) के नोआपाड़ा में शिक्षक रामनिरंजन सेन के घर में 22 मार्च 1894 को सूर्य सेन का जन्म हुआ था। 1916 में, राष्ट्रवाद की भावना से उत्साहित और कॉलेज में अपने शिक्षकों से प्रेरित होकर, वह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। वह असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रूप से शामिल हुए। उन्हें ब्रिटिश-विरोधी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार भी किया गया। जेल से रिहा होने के बाद, सूर्य सेन ने द इंडियन रिवोल्यूशनरी आर्मी नामक कार्यकर्ताओं के एक समूह का नेतृत्व किया। इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित संघर्ष का नेतृत्व करना और उनकी सत्ता को चुनौती देना था।

छापेमारी के लिए सूर्य सेन ने वहां के युवाओं को लामबंद और प्रशिक्षित करना शुरू किया। वह बम बनाने की कला में निपुण थे और क्रांतिकारियों के लिए विस्फोटक तैयार करने का जिम्मा संभालते थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन, गणेश घोष, प्रीतिलता वाडेदार और कुछ अन्य व्यक्तियों के नेतृत्व में, समूहों में विभाजित साठ से अधिक छात्रों ने चटगांव के औपनिवेशिक प्रशासन और उसके पूरे तंत्र पर एक सुनियोजित हमले की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था, चटगांव में सरकारी संचार प्रणाली को बाधित करना, पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारना और हथियार जुटाना। अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष शुरू करने के लिए जब्त किए गए हथियारों को क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के बीच वितरित किया जाना था।

वहां वे टेलीग्राम और रेलवे लाइनों को बाधित करने के साथ ही शस्त्रागार पर छापा मारने में सफल रहे। वहीं गोला-बारूद खोजने में उन्हें विफलता का सामना करना पड़ा। फिर भी, उन्होंने चटगांव को स्वतंत्र घोषित किया। वहां एक अस्थायी सरकार बनाने का दावा किया। युवाओं से इस आंदोलन में जुड़ने का अनुरोध किया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से ब्रिटिश अधिकारी हिल गए और पीछे हट गए। लेकिन कुछ ही समय में अंग्रेज और अधिक सशक्त होकर वापस आए एवं कार्यकर्ताओं का बेरहमी से दमन किया। सूर्य सेन और उनके अधिकांश सहयोगी जलालाबाद की पहाड़ियों में छिप गए। वहां के गांवों में सेन को लोगों का भारी समर्थन मिला। अपने ठिकाने से, उन्होंने औपनिवेशिक संपत्ति और अधिकारियों पर कई गुरिल्ला हमले किए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन पकड़े जाने से पहले लगभग 3 साल अंग्रेजों से बचने में सफल रहे।

12 जनवरी 1934 को, सेन और उनके सहयोगी तारकेश्वर दस्तीदार को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। अपने साथियों को लिखे अपने अंतिम पत्र में, उनकी लिखी कुछ पंक्तियां इस प्रकार थीं "मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मेरा मन अनंत काल की ओर उड़ानें भर रहा है... ऐसे सुखद, ऐसे गहन, ऐसे गंभीर क्षण में, मैं तुम्हारा पीछा क्या छोड़ूं? बस एक ही चीज है, वो है मेरा सपना, एक सुनहरा सपना- आजाद भारत का सपना..." ■

> *मास्टर सूर्य सेन को 1934 में जब फांसी दी गई, तब उन्होंने अपने साथियों को एक पत्र लिखा और पत्र में एक ही शब्द की गूंज थी और वह शब्द था वंदे मातरम्।* **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

सामर्थ्य को सशक्त करने का निरंतर प्रयास

शास्त्रों में कहा गया है - तत् त्वम असि! यानी जिस ब्रह्म की खोज मे हम निकले हैं, वो हम ही हैं, वो हमारे भीतर ही है। जो सामर्थ्य हमारे भीतर है उसे पहचानना है। बीते 11 वर्षों में भारत ने अपना वही सामर्थ्य पहचाना और इस सामर्थ्य को सशक्त करने के लिए आज देश निरंतर प्रयास कर रहा है। 27 फरवरी को न्यूज 18 राइजिंग भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 11 वर्षों में देश की चेतना में नई ऊर्जा का हुआ है प्रवाह...

सामर्थ्य किसी देश में अचानक पैदा नहीं होता, सामर्थ्य पीढ़ियों में बनता है। वो ज्ञान, परंपरा, परिश्रम और अनुभव से निखरता है। न्यूज 18 राइजिंग भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब किसी राष्ट्र के भीतर, छिपी हुई उसकी शक्ति जागती है तो वह नई उपलब्धियां हासिल करता है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आज पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बन चुका है।

एक समय था, जब भारत नई टेक्नोलॉजी का सिर्फ उपभोक्ता था। आज भारत नई टेक्नोलॉजी का निर्माता भी है और नए मानक भी स्थापित कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने अपने सामर्थ्य को पहचाना है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जब हम गर्व से आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया हमें जिस नजर से देखती रही है, वो नजर भी बदली है। कुछ साल पहले तक दुनिया में भारत के किसी इवेंट की कितनी कम चर्चा होती थी और उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। आज भारत जो करता है, जो एक्शन यहां होते हैं, उसका वैश्विक विश्लेषण होता है। एआई समिट इसका उदाहरण है।

शिपिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती

भारत हर साल विदेशी समुद्री जहाजों से माल ढुलाई के लिए किराए पर 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करता है। फर्टिलाइजर के आयात पर हर साल सवा दो लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। पेट्रोलियम आयात पर हर साल 11 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यानी हर वर्ष लाखों करोड़ रुपये देश से बाहर जा रहे हैं। विदेशी जहाजों को 6 लाख करोड़ रुपये न देना पड़े इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय शिपिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। फर्टिलाइजर का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए नए प्लांट लग रहे हैं, नैनो-यूरिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सोलर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्राथमिकता दी जा रही है।

> हमने मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया, मेक इन इंडिया पर बल दिया, अपनी बैंकिंग सिस्टम को सशक्त किया, महंगाई को कंट्रोल किया और भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाया। भारत का यही सामर्थ्य है कि दुनिया के विकसित देश सामने से भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं।
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

स्वस्थ भारत की मजबूत नींव

केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय के तहत राजस्थान के अजमेर से राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है ताकि महिलाओं को बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाया जा सके। अभी तक सरकार 12 तरह की बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि सार्वभौमिक टीकाकरण 99% तक पहुंच गया है। आइए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (16 मार्च) पर समझते हैं कि कैसे टीकाकरण ने बच्चों और माताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जनस्वास्थ्य को दिया है मजबूत आधार...

भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2026 को तीन महीने का राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। अब केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के सहयोग से देश भर के सभी सरकारी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला और उप-जिला अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में 14 वर्ष की किशोरियों को यह टीका मुफ्त दिया जाएगा। अभियान की लॉन्च की तारीख से 90 दिनों के भीतर 15 साल की होने वाली लड़कियां भी इस तीन महीने के विशेष एचपीवी टीकाकरण अभियान के दौरान टीका लगवाने के लिए पात्र होंगी।

लगभग एक करोड़ 15 लाख किशोरियां वर्तमान में इस टीके के लिए पात्र हैं। अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 90 दिनों का टीकाकरण अभियान प्रतिदिन चलाया जाएगा और इसके बाद नियमित टीकाकरण दिवसों पर भी यह उपलब्ध रहेगा। यह राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने और देश भर में माताओं और बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐतिहासिक अभियान के साथ, भारत एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम चलाने वाले 160 से अधिक देशों में शामिल हो गया है।

हर साल, यूआईपी के तहत 2.6 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लगता है टीका। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे का उसके जीवन के पहले वर्ष में पूरी तरह से टीकाकरण किया जाए।

राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान से न सिर्फ बच्चे और माताएं सुरक्षित हो रही हैं बल्कि इससे स्वस्थ भारत की भी नींव पड़ रही है। इस नींव को मजबूत करने में संपूर्ण टीकाकरण कवरेज के लिए वर्ष 2014 में शुरू की गई मिशन इंद्रधनुष की बड़ी भूमिका है। करीब 99 प्रतिशत टीकारकण के लक्ष्य को प्राप्त करने में एआई जैसे टेक्नोलॉजी ने काफी मदद की है। टेक्नोलॉजी कितनी प्रभावी रही है

दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौत में 25 फीसदी मौतें भारत में होती हैं। भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है, जिसमें हर वर्ष लगभग 80 हजार नए मामले सामने आते हैं और 42 हजार से अधिक महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।

'नारी शक्ति' को सशक्त बनाने और माताओं तथा बेटियों के स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सभी जानते हैं कि जब परिवार में मां बीमार पड़ती है, तो घर बिखर जाता है। मां स्वस्थ रहती है, तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भावना के साथ सरकार ने महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधामनंत्री

देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास...

- राज्य, जिला और ब्लॉक टीकाकरण कार्यबल नियमित रूप से चलाए जाने वाले टीकाकरण अभियानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं।
- टीकाकरण कवरेज में सुधार के उपायों के रूप में जागरूकता, सामाजिक लामबंदी, पारिवारिक स्तर पर आपसी संवाद और मीडिया सहभागिता जैसे रणनीतिक क्रियाकलाप किए जाते हैं।
- व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष कैच-अप टीकाकरण अभियान, सघन मिशन इंद्रधनुष, कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों में छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए चलाया गया।
- पल्स पोलियो कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनआईडी) जैसे विशेष टीकाकरण अभियान हर वर्ष चलाए जाते हैं।
- टीकाकरण गतिविधियों के लिए निर्धारित दिनों पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वीएचएनडी) का आयोजन किया जाता है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के सभी टीकाकरण कार्यक्रमों के डिजिटल पंजीकरण और रिकॉर्डिंग के लिए यू-विन पोर्टल शुरू किया है।

इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि 8 फरवरी 2026 तक यू-विन पोर्टल पर 11.12 करोड़ से अधिक बच्चे और 3.78 करोड़ गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हैं।

अब 13 तरह की बीमारियों से बचाव के लिए देश में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 12 बीमारियों के खिलाफ जिसमें सवाईकल कैंसर, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बाल्यावस्था का गंभीर तपेदिक (TB), रोटावायरस डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और न्यूमोकोकल के कारण होने वाला निमोनिया शामिल है। वहीं जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) के खिलाफ उन जिलों में टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं जो जिले इस बीमारी से प्रभावित हैं। ■

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल हब बनता भारत

आवरण कथा

जब भारत आगे बढ़ता है, तो दुनिया भी आगे बढ़ती है। इसी सोच के साथ भारत ने दुनिया के सामने 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के मंत्र को अपनाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में मानवीय और समावेशी नेतृत्व का परिचय दिया है। इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट 2026 में 'मानव' विजन के माध्यम से भारत ने दिखाया कि नई तकनीक का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए कैसे किया जा सकता है। यह वैश्विक सम्मेलन इस बात का प्रमाण बना कि भारत के पास एआई क्रांति का नेतृत्व करने की क्षमता भी है और सामर्थ्य भी...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एआई इंपैक्ट समिट में अपना संबोधन दे रहे थे, तब रीयल टाइम पर एआई का टूल मूक-बधिरों के लिए जनरेटेड वीडियो के माध्यम से सांकेतिक भाषा में उनका यह भाषण शब्दश: पहुंचा रहा था।

न्यायपालिका के लिए जेनरेटिव एआई आधारित लीगल रिसर्च एनालिटिक्स टूल विकसित किया गया है। पायलट मोड वाले इस टूल में शामिल एआई बॉट सर्वोच्च न्यायालय के 1950 के आगे के निर्णयों या प्रश्नों के उत्तर देता है।

एआई विनहगम दृष्टि एक जियोस्पेशियल इमेज एनालिटिक्स सेवा है जो क्षेत्र का अनुमान लगाकर योजना बना सकती है। इस सेवा का उपयोग 30 हजार गांवों के लिए कंक्रीट की छतों की पहचान करने और सोलर पैनल के लिए क्षेत्र का अनुमान लगाने में किया गया।

ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है। वहां जो कुछ बोला जा रहा है या जो वीडियो बनाए गए हैं, उनके इनपुट से मिनिट्स सहित पूरी जानकारी एक सार के रूप में एआई से जुड़ा एप 'सभासार' 14 भाषाओं में पेश करता है।

देश में कहीं चक्रवात या आपदा आए तो आईआईटी मुंबई द्वारा विकसित स्पेशली अवेयर डोमेन एडाप्टेशन नेटवर्क मॉडल हवाई तस्वीरों के जरिये नुकसान का सटीक अंदाजा लगा लेता है। कम डेटा होने की दशा में भी सही परिणाम दे सकता है जिससे आपदा के समय में तेजी से और भरोसेमंद तरीके से मदद पहुंचाई जा सकती है।

भारत में एआई के यह समाधान दिखाते हैं कि आज न्यायपालिका से भाषा की सुविधा तक, आपदा से लेकर लिखने-पढ़ने तक, किसान से लेकर डॉक्टर तक, छात्र से लेकर स्टार्टअप तक, महिला से लेकर युवा तक सभी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पहुंच रहा है। भारत एआई सुपर पावर बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी तकनीक क्रांति-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अब भारत से निर्देशित होने वाली है, जो केवल एक तकनीक नहीं बल्कि बन चुका है भारत की आर्थिक ताकत का नया इंजन। भारत में एआई का प्रयोग दुनिया के अन्य देशों से बिलकुल अलग है। दुनिया जहां अपनी ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से एआई तकनीक में निवेश करती है, वहां भारत 'सबका साथ-सबका विकास' के विजन पर काम करते हुए समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति और संपूर्ण मानवता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से तकनीक के विकास के काम में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन स्पष्ट है कि तकनीक केवल विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर युवा, हर किसान, हर उद्यमी, हर छात्र के लिए हो, इसलिए भारतीय एआई है एआई फॉर ऑल यानी एआई जैसी तकनीक सभी के लिए।

भारत अपनी विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण चरण में है। एआई इस विकास के एक महत्वपूर्ण सहायक के रूप में उभर रही है। भारत में इस समय 60 लाख से अधिक टेक और एआई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। 1,800 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में से 500 से अधिक केवल एआई पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा एआई टैलेंट हब बन रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि करीब 2 लाख स्टार्टअप में से 89 प्रतिशत अपने समाधान में एआई का प्रयोग कर रहे हैं। नैस्कॉम के अनुसार 87 प्रतिशत भारतीय एंटरप्राइज कंपनियां एआई को अपना चुकी है। देश की कुल एआई मूल्य का 60 प्रतिशत हिस्सा ऑटोमोबाइल, रिटेल, बीएफएसआई और हेल्थकेयर के चार सेक्टरों में है। लेकिन असली गेमचेंजर है- इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई डेटा सेंटर्स में लगभग 70 बिलियन डॉलर का निवेश जारी है और 90 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त निवेश घोषित किया जा चुका है। यह तो केवल शुरुआत है। आम बजट 2026-27 में एआई

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

> *आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आज जो हम देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके इंपैक्ट का सिर्फ प्रारंभिक संकेत है। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक, मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। अंतर सिर्फ एक है, इस बार स्पीड भी अभूतपूर्व है और स्केल भी अप्रत्याशित है।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इस बजट में क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 यानी जब तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तब तक के लिए टैक्स छूट प्रस्तावित है। डेटा सेंटर प्रदाताओं के लिए 15 प्रतिशत सेफ हार्बर यानी कानूनी रूप से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जिसकी सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्या है?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वह तकनीक है, जिसकी मदद से मशीनें ऐसे काम कर सकती हैं जो सामान्य तौर पर इंसानी समझ और सोच की जरूरत रखते हैं। यह मशीनों को अनुभव से सीखने, नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाती है। एआई डेटा और विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से जानकारी का विश्लेषण करती है, पैटर्न पहचानती है और उसी आधार पर जवाब या निर्णय देती है। समय के साथ यह अपने काम में सुधार भी करती जाती है, जिससे वह इंसानों की तरह तर्क करने, निर्णय लेने और बातचीत करने में अधिक सक्षम हो जाती है।

एआई समिट का उद्देश्य और थीम : इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की थीम-सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, अर्थात् सभी का कल्याण, सभी की प्रसन्नता। इसका उद्देश्य भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है जहां एआई मानवता को आगे बढ़ाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे और हमारी साझा धरती की रक्षा करे।

> *समिट में सीईओ राउंड टेबल में एआई, प्रौद्योगिकी और नवाचार जगत के विभिन्न हितधारक एक साथ आए। जिनका ध्यान एआई को जिम्मेदारी से विस्तारित करने, वैश्विक सहयोग को मजबूत करने और विकास के अवसरों को खोलने पर केंद्रित था। मानव प्रगति और सतत विकास के लिए एआई का उपयोग करने की साझा प्रतिबद्धता देख उत्साह महसूस हुआ।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

करोड़ रुपये की गई है। यानी केंद्र सरकार एआई के लिए देश में पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है। इसी दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल है- इंडिया एआई इंपैक्ट समिट। भारत ने 16-20 फरवरी 2026 तक दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट की सफल और ऐतिहासिक मेजबानी की। यह एआई के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व की घोषणा है।

नई दिल्ली एआई घोषणा-पत्र को विश्व ने अपनाया

नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट घोषणा पत्र को दुनिया ने अपनाने का फैसला किया। भारत ने बराबरी, पहुंच और वैश्विक सहयोग पर आधारित 'सबके लिए एआई' की मांग को आगे बढ़ाया है। नई दिल्ली घोषणा-पत्र को 91 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर काम करने वाले, भरोसेमंद, मजबूत और प्रभावी एआई के लिए साझा ग्लोबल विजन का समर्थन किया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहयोग में मील का पत्थर है।

एआई के लिए साझा ग्लोबल विजन

"सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" (सबका कल्याण, सबकी खुशी) के सिद्धांत से प्रेरित, घोषणा इस बात पर जोर देती है कि एआई के फायदे को पूरी मानवता के साथ बराबरी से साझा किया जाना चाहिए। यह इन बातों पर देती है जोर...

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय हितधारकों के साथ जुड़ाव को मजबूत करना।
- राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करना।
- सुलभ व भरोसेमंद फ्रेमवर्क के जरिए एआई को आगे बढ़ाना।

जिम्मेदार एआई अपनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगों को लेकर सिर्फ इनोवेशन ही नहीं कर रहा है बल्कि जिम्मेदार एआई अपनाने के लिए संकल्पबद्ध भी है। इसी कड़ी में भारत के नाम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ जिसमें 24 घंटे के दौरान 2,50,946 लोगों ने जिम्मेदार एआई के लिए प्रतिज्ञा ली। राष्ट्रव्यापी अभियान में छात्रों और नागरिकों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह एआई उपयोग के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया गया।

स्टार्टअप पुस्तक : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में एआई इंपैक्ट स्टार्टअप पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक भारत के एआई और डीप-टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का अध्ययन है।

भविष्य में निवेश

आने वाले वर्षों में एआई के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, मूलभूत मॉडल, हार्डवेयर और अनुप्रयोगों से संबंधित निवेश में सैकड़ों अरब डॉलर निवेश होने की है उम्मीद...

110 अरब डॉलर का निवेश रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 7 वर्ष में करेगा।

15 अरब डॉलर का निवेश गूगल की ओर से विशाखापट्टनम में की जाएगी।

100 अरब डॉलर का निवेश वर्ष 2035 तक अदानी एंटरप्राइजेज ने करने की बात कही है।

- 5 अरब डॉलर का जनरल कैटलिस्ट 5 वर्ष में करेगा।
- 10 अरब डॉलर का निवेश लाइट्स्पीड वेंचर पार्टनर्स करेगा।
- 11 अरब डॉलर का निवेश महाराष्ट्र में टाटा समूह करेगा।

एआई ग्लोबल परिदृश्य में भारत की नई पहचान

शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणां तथा।
ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ॥"

अर्थात्, बुद्धिमत्ता, तर्कशीलता और निर्णय-क्षमता विज्ञान और टेक्नोलॉजी को जन-जन के लिए उपयोगी बनाती हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट- 2026 का उद्देश्य भी यही रहा कि कैसे एआई का इस्तेमाल सर्वजन के हित में हो। इसलिए इस समिट की थीम- सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, अर्थात सभी का कल्याण, सभी की प्रसन्नता पर आधारित था। इसमें कोई संदेह नहीं कि एआई की दुनिया में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिसका साक्षी बना है 2026 का ग्लोबल समिट। यह समिट एआई ग्लोबल परिदृश्य में भारत की नई पहचान बनकर उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ग्लोबल इकोनॉमी और रोजगार का सबसे बड़ा गेमचेंजर है। दुनिया के लिए एआई का एक ही मतलब है- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन भारत

वर्ष 2032 तक 131 अरब डॉलर से ज्यादा का होगा भारत का एआई बाजार

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई के वैश्विक बाजार का आकार 2020 में 103.6 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 288.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसी अवधि में, भारत में एआई बाजार 2.97 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 7.63 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारतीय एआई बाजार के 2032 तक 42.2% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) से बढ़कर 131.31 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

एआई समिट में 118 से ज्यादा देश शामिल

एआई इंपैक्ट समिट में 118 देशों के 5 लाख से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 20 से अधिक देशों के सरकार प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल हुए। 100 से ज्यादा ग्लोबल एआई लीडर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएक्सओ और 500 से ज्यादा बड़े एआई विशेषज्ञ शामिल हुए।

स्वास्थ्य में एआई का बढ़ता उपयोग

- इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में दो नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों-**SAHI** (भारत में स्वास्थ्य सेवा के लिए एआई रणनीति) और **BODH** (स्वास्थ्य एआई के लिए ओपन डाटा प्लेटफॉर्म) की शुरुआत की गई। यह पहल भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के सुरक्षित, नैतिक और प्रमाण-आधारित उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

मेडिकल इमेज (जैसे एक्स-रे या स्कैन) के एआई विश्लेषण से टीबी, कैंसर और अन्य बीमारियों का सटीक तरीके से पता लगाया जा सकता है।

- एआई स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सुलभ बना रहा है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में।
- एआई से जुड़े जांच उपकरण बीमारियों की पहचान में मदद करते हैं।
- एआई आधारित टेलीमेडिसिन ग्रामीण मरीजों को डॉक्टरों से जोड़ती है, जिससे यात्रा और इंतजार का समय कम होता है।
- एआई बीमारी के फैलाव की पहले से चेतावनी देने में मदद करता है।
- दवाओं की खोज और मरीज के अनुसार उपचार तय करने में भी सहायक।

भारत-फ्रांस का स्वास्थ्य एआई केंद्र

दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में फ्रांस के राष्ट्रपति की मौजूदगी में इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ (आईएफ-सीएआईएच) की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य एआई आधारित अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा तथा इनोवेशन को प्रोत्साहित करते हुए जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान निकालना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि भारत और फ्रांस उन्नत कम्प्यूटिंग क्षमता तथा प्रतिभा विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि हम अपने विश्वसनीय एआई तंत्र स्वयं विकसित कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि केवल उन तकनीकों पर निर्भर नहीं रह सकते जो अन्य देशों द्वारा निर्मित व संचालित हों।

के लिए इसके दो अर्थ हैं- आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया। इसे साकार करने का सबसे बड़ा अवसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के क्षेत्र में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है। इसी एआई क्षमता का उद्घोष बना है यह समिट। यह समिट किसी भी विकासशील देश में आयोजित पहला ग्लोबल एआई समिट है। इस समिट के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा जैसे कई वैश्विक नेता के साथ 15 से 20 शासन प्रमुख, 50 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मंत्री समेत 100 से ज्यादा देश शामिल हुए। गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम आल्टमैन जैसे बड़े नाम शामिल हुए। यह समिट देश के लिए ऐतिहासिक अवसर बना, जो एआई के क्षेत्र में बदलाव और विकास को नई रफ्तार देगा। एकेडमी, स्टार्टअप और सरकारों के साथ मजबूत सहयोग स्थापित होगा। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा मिलेगा।

महिला नेतृत्व वाले एआई

इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में जन कल्याण और डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महिला नेतृत्व वाली एआई का प्रदर्शन किया गया। इसमें समावेशी, विस्तार योग्य और इंपैक्ट-फर्स्ट एआई समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए महिला नेतृत्व वाले दस स्टार्टअप को सम्मानित किया गया।

कृषि में एआई का उपयोग

उपग्रह से मिली तस्वीरों, मौसम के पूर्वानुमान, मिट्टी की जानकारी और फसलों के पैटर्न का विश्लेषण करके एआई किसानों को यह समझने में मदद करता है कि कौन-सी फसल बोनी है, कब बोनी है, कितनी खाद डालनी है और कटाई का सही समय क्या है। कीट और बीमारियों की समय रहते चेतावनी देने से लेकर सिंचाई और उर्वरकों की बेहतर योजना बनाने तक, एआई खेती को अधिक सटीक, प्रभावी और कम जोखिम वाली बनाता है।

- नया डिजिटल साथी "भारत-VISTAAR" लांच किया गया। यह एआई आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को फोन कॉल, चैटबॉट और आगे चलकर एप के जरिए मौसम, मंडीभाव, कीट-रोग, मिट्टी, फसल सलाह और योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर देगा। किसान अभी 155261 नंबर डायल कर जो सवाल पूछेंगे, तुरंत उसका समाधान मिलेगा।

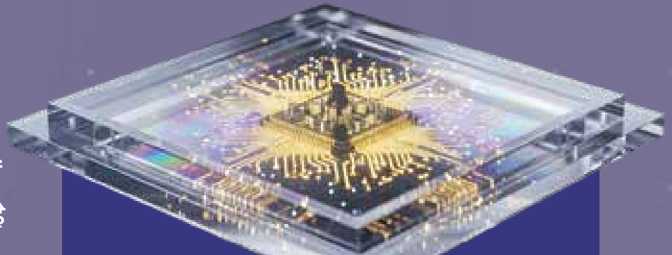

राष्ट्रीय एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी मजबूती

भारत सरकार ने राष्ट्रीय एआई ढांचे को मजबूत करने के लिए मौजूदा 38,000 जीपीयू के अलावा 20,000 और जीपीयू जोड़ने का फैसला किया है। इसकी घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में की। जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) एक शक्तिशाली कंप्यूटर चिप होती है। यह मशीनों को तेजी से डाटा समझने, तस्वीरें प्रोसेस करने, एआई प्रोग्राम चलाने और जटिल कामों को सामान्य प्रोसेसर की तुलना में अधिक तेजी और दक्षता से करने में मदद करती है।

सरकारी सेवाओं में बदलाव के लिए एआई का प्रयोग होगा। जिम्मेदार और नैतिक एआई की प्रतिबद्धता के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क बनेगा।

भारत के 'मानव' विजन से प्रेरित एआई

फरवरी में आयोजित इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट दुनिया के लिए नई तकनीक के लोकतंत्रीकरण, मानव कल्याण के लिए इसका प्रयोग और सुशासन-सुरक्षा की जवाबदेही का आधार बना। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने मानव विजन को दुनिया के सामने रखा। इसका अर्थ है- एआई रोजगार का दुश्मन नहीं, सहयोगी बने, गांव और गरीब तक पहुंचे, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करे, छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाए। भारत का मॉडल पश्चिमी देशों से अलग है। यहां एआई को केवल व्यापारिक लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखा जा रहा है।

पीएम मोदी ने एआई के लिए भारत के 'मानव' (MANAV)

...ताकि अवसरों का उठाया जा सके लाभ

विद्यालयों में बुनियादी एआई साक्षरता

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में डिजिटल और एआई साक्षरता को आवश्यक योग्यता जैसी प्राथमिकता दी गई है।
- एआई व कम्प्यूटेशनल थिंकिंग पहल के तहत ग्रेड 3 से शुरू।
- एआई के साथ उन्नति के लिए युवा एआई में कक्षा 8-12 के छात्रों को आठ विषय परक क्षेत्रों में व्यावहारिक एआई समाधान तैयार करने में सहायता मिलती है।
- सभी के लिए युवा एआई के तहत 11 भाषाओं में एक निःशुल्क राष्ट्रीय एआई साक्षरता पाठ्यक्रम तैयार है, इसका लक्ष्य 1 करोड़ नागरिकों को एआई की बेसिक जानकारी देना है।

शिक्षा में एआई का उपयोग

एआई शिक्षा को पर्सनलाइज्ड, समावेशी और आसान बना रहा है। एआई आधारित प्लेटफॉर्म हर छात्र की जरूरत और सीखने की गति के अनुसार पढ़ाई की सामग्री तैयार करता है। इससे धीमी गति से सीखने वाले और तेज सीखने वाले दोनों को बराबर मदद मिलती है। एआई की मदद से भाषा अनुवाद भी आसान हो गया है, जिससे पढ़ाई की सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हो पाती है। एआई आधारित ट्यूटरिंग सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और 24 घंटे सीखने में सहायता करते हैं। DIKSHA जैसे प्लेटफॉर्म भी एआई का उपयोग करके अलग-अलग समूहों के छात्रों के लिए उपयोगी और सरल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार ने आईआईटी मद्रास में एआई फॉर एजुकेशन के लिए एक केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है।

व्यावसायिक और उद्योग से जुड़े प्रशिक्षण

- कौशल भारत मिशन और एसओएआर पहल में स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस के तहत दिसंबर 2025 तक निजी साझेदारी में 1.34 लाख छात्र और शिक्षकों को प्रशिक्षण।
- भारत को अत्याधुनिक डिजिटल प्रतिभा राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एआई, बिग डेटा अनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, ब्लॉक चेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और दूसरी नई प्रौद्योगिकी में कौशल विकास, पुनः कौशल विकास, उन्नत कौशल विकास से जुड़े कोर्स यहां उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **http://futureskillsprime.in/** पर योग्यता और आकांक्षाओं के अनुरूप कौशल प्रमाणपत्र लिए जा सकते हैं। अभी तक 26.2 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है जिनमें से 16.6 लाख को प्रशिक्षित किया गया है।
- स्किल इंडिया डिजिटल हब विभिन्न शिक्षार्थियों की दक्षताओं के अनुरूप प्रारंभिक से लेकर उन्नत स्तर तक के एआई और मशीन लर्निंग पाठ्यक्रम प्रदान करता है ताकि प्रत्येक इच्छुक पेशेवर एआई-केंद्रित करियर की ओर अग्रसर हो सके।

विजन को प्रस्तुत किया। उन्होंने 'मानव' का अर्थ इस तरह से समझायाः

- **एम- मोरल एंड एथिकल सिस्टमः** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैतिक दिशा-निर्देशों पर आधारित होनी चाहिए।
- **ए- अकाउंटेबल गवर्नेंसः** पारदर्शी नियम और सशक्त निगरानी।
- **एन- नेशनल सॉवरेन्टीः** डेटा उसके असली स्वामी का है।
- **ए- एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिवः** एआई को एकाधिकार नहीं, बल्कि गुणक बनना चाहिए।
- **वी- वैलिड एंड लेजिटीमेटः** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानूनी और सत्यापन योग्य होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट कहना था कि भारत का यह मानव विजन 21वीं सदी की एआई-संचालित दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। उन्होंने स्मरण कराया कि दशकों पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इससे कितने रोजगार सृजित होंगे। यही

उन्नत एआई प्रतिभा और अनुसंधान इको-सिस्टम

- इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्रों के लिए फेलोशिप और विशेष कौशल-संवर्धन पाठ्यक्रमों के माध्यम से एआई इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है।
- इंडिया एआई फ्यूचरस्किल्स में दिसंबर 2025 तक 500 पीएचडी शोधार्थियों, 5,000 स्नातकोत्तर छात्रों और 8,000 स्नातक छात्रों को सहायता दी जा रही है। इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।
- टियर-2/3 शहरों में 27 इंडिया एआई डेटा और एआई लैब स्थापित किए गए हैं ताकि एआई, डेटा और संबंधित क्षेत्रों जैसे डेटा एनोटेशन, डेटा क्यूरेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा साइंस से जुड़े पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा सकें।
- देश की आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 543 अतिरिक्त इंडिया एआई डेटा और एआई लैब को स्वीकृति दी गई है। इससे महानगरों से परे एआई क्षमताओं का समान वितरण सुनिश्चित होगा।

फाइनेंस और कॉमर्स में एआई

बैंकिंग चैटबॉट

बैलेंस चेक और फंड ट्रांसफर जैसी रूटीन सर्विस के लिए 24/7 मदद देते हैं, जिससे इंतजार का समय कम होता है।

- एआई फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनक्लूजन और सर्विस एफिशिएंसी को मजबूत कर रहा है।
- एआई-पावर्ड सिस्टम रियल टाइम में फ्रॉड का पता लगाता है और डिजिटल ट्रांजैक्शन को सिक्योर करता है।
- एआई-बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग से बिना बैंक वाले और कम सुविधा वाले लोगों के लिए लोन तक पहुंच बढ़ती है।
- एआई-ड्रिवन पर्सनलाइजेशन से कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सलाह मिलती है।

शासन एवं सार्वजनिक सेवाओं में एआई

- एआई सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता, सुलभता और पारदर्शिता को बढ़ा रहा है।
- न्यायालय के निर्णयों का स्थानीय भाषाओं में एआई की सहायता से अनुवाद न्याय तक पहुंच बनाता है।
- एआई योजनाओं और आवेदनों की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करता है। न्यायपालिका में भी एआई केस प्रबंधन और कानूनी पहुंच को बेहतर बनाता है।

एआई से ट्रैफिक, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाया जा रहा है।

स्थिति आज एआई के संदर्भ में भी है क्योंकि भविष्य में किस प्रकार के रोजगार सृजित होंगे, इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। एआई के प्रयोग से उसके भविष्य की दिशा निर्धारित होगी और इस संदर्भ में पीएम मोदी ने कहा कि एआई में कार्य का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि सामूहिक निर्णयों और कार्यों पर निर्भर करेगा। इस मंच से भारत ने संदेश दिया कि एआई का सही प्रभाव तभी दिखेगा, जब सही समय पर, सही नियत से, सही निर्णय लिए जाएं।

'एआई फॉर ऑल' से विकसित भारत का निर्माण

भारत ने एआई फॉर ऑल की भावना से प्रेरित होकर सरकार के कार्यक्रम तय किए हैं, ताकि एआई की क्षमता का पूरा लाभ उठाया जा सकें। पीएम मोदी का विजन स्पष्ट है कि एआई केवल बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि एआई फॉर इंडिया का मतलब एआई फॉर ऑल है। भारत में एआई का लोकतंत्रीकरण समावेशी विकास की नई आधारशिला रख रहा है। अब विकसित भारत की यात्रा का

चक्रवात की निगरानी

- भारतीय मौसम विभाग समुद्री तूफानों और चक्रवातों पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करता है। तूफान कितना ताकतवर है, इसका पता लगाने में एडवांस्ड ड्वोरक तकनीक मदद करती है। साथ ही, आईएमडी मौसम की भविष्यवाणी करने वाले यूरोपीय केंद्र (यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्टिंग) से मिलने वाले एआई बेस्ड गाइडेंस का भी उपयोग करता है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 22 पेटाफ्लॉप्स की भारी क्षमता वाले हाई-पावर कंप्यूटिंग सिस्टम (सुपर कंप्यूटर) लगाए हैं। इस सिस्टम का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा खासतौर पर एआई के कामों के लिए इस्तेमाल होता है।

- इसके अलावा, मौसम की भविष्यवाणी में एआई और मशीन लर्निंग रिसर्च के लिए अलग से ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगाए गए हैं।
- ये शक्तिशाली सिस्टम मौसम का और भी सटीक अनुमान लगाने वाले मॉडल तैयार करने में मदद करते हैं।

भूस्खलन, बाढ़ और ग्लेशियर की निगरानी

- भारत में विकसित स्वदेशी एआई-आधारित भूस्खलन चेतावनी प्रणाली अब पहाड़ खिसकने से तीन घंटे पहले ही अलर्ट दे देती है। इसकी सटीकता 90 प्रतिशत से भी अधिक है। हिमाचल प्रदेश में 60 से अधिक स्थानों पर इसे लगाया गया है।
- इसरो द्वारा वित्तपोषित (2021-24) इंडियन लैंड डेटा एसिमिलेशन सिस्टम (आईएलडीएएस), रिमोट सेंसिंग और विशेष कंप्यूटर मॉडल्स की मदद से जमीन की स्थिति और बाढ़ के संभावित इलाकों का सटीक अनुमान लगाता है।
- **BrahmaSATARK** ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए बाढ़ का पूर्वानुमान देता है जबकि **GBM-CLIMPACT** एक ऐसा टूलकिट है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना बेसिन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और जल क्षेत्र की तैयारी का आकलन करता है।
- एआई आधारित सिस्टम मिलकर खतरे की चेतावनी समय से पहले देती है, जिससे लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाना आसान हो जाता है।
- एआई की मदद से इमारतों और बिजली-पानी जैसे बुनियादी ढांचे के नुकसान को कम किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील इलाकों में रहने वाले समुदायों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

महत्वपूर्ण स्तंभ है- एआई फॉर ऑल। भारत एआई को लोकतांत्रिक बना रहा है। यानी सस्ती कंप्यूटिंग पावर और ओपन डाटा तक आसान पहुंच। एआई के लोकतंत्रीकरण का अर्थ है- एआई क्षमता, उपकरण और लाभ का समान वितरण। यह केवल मुट्ठी भर टेक विशेषज्ञ या कंपनी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एआई जैसी विशेष तकनीक का लाभ हर स्टार्टअप, हर शोधकर्ता, हर छात्र और हर राज्य तक पहुंचे। इसलिए भारत आज इंडिया एआई मिशन के माध्यम से एआई रिसर्च, स्किलिंग और कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के कोने-कोने तक पहुंचा रहा है। डेटा सेंटर्स से लेकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक, भारत मजबूत एआई इकोसिस्टम बना रहा है। जिसका जमीनी असर भी दिख रहा है। एआई से किसानों को सही मौसम की जानकारी, छात्र को पर्सनल लर्निंग, डॉक्टर को सटीक डायग्नोसिस और स्टार्टअप को वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ताकत मिल रही है। भारत का संकल्प है- एआई फॉर ऑल। एआई

जलवायु और मौसम की भविष्यवाणियों के लिए नए एआई टूल्स

- मौसम जीपीटी (Mausam GPT) नामक एक एआई चैटबॉट विकसित किया जा रहा है जो किसानों और अन्य लोगों को जलवायु और मौसम के बारे में सलाह देगा।
- बारिश के पैटर्न का पूर्वानुमान लगाने और भविष्यवाणी करने के लिए एआई अनुसंधान कर रही है।
- एआई का उपयोग अब आग की घटनाओं, कोहरा, बिजली गिरने और गरज के साथ तूफान आने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा रहा है।
- डीप लर्निंग तकनीक मौसम में बारिश की सटीक भविष्यवाणियों को बेहतर बनाने में मदद करती है।

एआई के साथ बदलता भारत

इंडिया एआई मिशन के लिए पांच वर्षों के दौरान 10,300 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित और 38,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) समावेशी नवाचार को सक्षम बना रहे हैं।

60 लाख लोग प्रौद्योगिकी और एआई इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं।

इस वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजस्व के 280 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार जाने का अनुमान है।

1.7 ट्रिलियन डॉलर एआई भारत की अर्थव्यवस्था में जोड़ सकता है वर्ष 2035 तक।

दैनिक जीवन और कार्य में एआई

- एआई इनोवेशन की एक नई लहर चल रही है जो दैनिक जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य सेवा और कृषि से लेकर शिक्षा, शासन, और जलवायु पूर्वानुमान तक।
- यह चिकित्सकों को तेजी से रोगों का निदान करने में मदद करती है। किसानों को डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। छात्रों के ज्ञानार्जन में सुधार करती है और शासन को अधिक कुशल तथा पारदर्शी बनाती है।
- इस परिवर्तन के केंद्र में बड़ा भाषा मॉडल (एलएलएम - लार्ज लैंग्वेज मॉडल) है। यह एक उन्नत एआई प्रणाली है जो विशाल डेटा से सीख कर मनुष्य के समान टैक्स्ट को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम होती है।
- भारत का एआई दृष्टिकोण केवल प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं है। यह समावेशन और सशक्तीकरण पर केंद्रित है। राष्ट्रीय पहलों और वैश्विक सहयोग के माध्यम से, एआई का उपयोग वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को हल करने, सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने और हर नागरिक के लिए अवसरों को अधिक सुलभ बनाने में किया जा रहा है।

बाई इंडिया, एआई फॉर द वर्ल्ड और यही है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का सच्चा लोकतंत्रीकरण। यही है नए भारत की पहचान, जहां विकास के केंद्र में है मानवता के कल्याण के लिए तकनीक का प्रयोग। भारत की एआई क्रांति की विशेषता दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अलग है। यहां एआई को केवल आर्थिक लाभ के नजरिए से नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव के सशक्त उपकरण के रूप में अपनाया जा रहा है।

मानव-केंद्रित तकनीक की ओर बढ़ता भारत

वर्ष 2026 में आयोजित एआई इंडिया इंपैक्ट समिट केवल एक तकनीकी आयोजन नहीं, बल्कि उस नए भारत की तस्वीर है जो तकनीक को मानवता और समाज की सेवा से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल बदलाव की जो यात्रा शुरू की थी, वह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बड़े विजन में बदल चुकी है। सरल शब्दों में कहें तो एआई यानी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस... सशक्त भारत

एआई की जोखिमों को कम करने वाले कानून

स्वचालित निर्णयों में एआई के बढ़ते उपयोग से भ्रम, पूर्वाग्रह, गलत सूचना और डीपफेक जैसे खतरे पैदा हो रहे हैं। भारत का मानना है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए कानून बनाने के साथ-साथ एआई शासन को नई और उन्नत तकनीकों से भी सशक्त बनाना आवश्यक है, ताकि प्रभावी और सुरक्षित व्यवस्था की जा सके सुनिश्चित...

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

- गलत सूचना, डीपफेक से धोखाधड़ी या पहचान की चोरी, धोखधड़ी के लिए कंप्यूटर उपयोग, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी क्षेत्र की छवि को कैप्चर करने, प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं।
- अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जो डीपफेक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तैयार किए जा सकते हैं, इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023

- बीएनएस की धारा 111 में किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह द्वारा संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से आर्थिक अपराध, साइबर अपराध सहित किसी भी गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने पर उसे दंडित करने का प्रावधान है।
- बीएनएस की अलग-अलग धाराओं में भी मानहानि, धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

- डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम, 2025 को 13 नवंबर, 2025 को अधिसूचित किया गया है।
- इस अधिनियम में डिजिटल वैयक्तिक डेटा की सुरक्षा का दायित्व डेटा फिड्युशरीज को सौपा गया है, उन्हें जवाबदेह बनाया गया है।
- यह नागरिकों को अपने डेटा पर नियंत्रण प्रदान करता है। कोई भी एजेंसी सहमति के बिना डेटा का उपयोग नहीं कर सकती।
- एसपीडीआई नियम में प्रावधान है कि बताए गए उद्देश्य के लिए ही डेटा उपयोग किया जाना चाहिए। किसी तीसरे पक्ष को डेटा देने से पहले पूर्व सहमति आवश्यक है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जो मशीनों को सोचने और सीखने की क्षमता देती है। जिस तरह मनुष्य अनुभव से सीखता है, पैटर्न पहचानता है और निर्णय लेता है, उसी तरह एआई सिस्टम भी डेटा के आधार पर सीखते हैं और निर्णय लेते हैं। उदाहरण के रूप में ऐसे समझे कि जैसे आपके मोबाइल का फेस अनलॉक, गूगल मैप पर ट्रैफिक की जानकारी, ऑनलाइन शॉपिंग में आपके लिए सुझाव, चैटबॉट द्वारा जो जवाब मिलते हैं, यह सभी एआई के रूप हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम से कंप्यूटर भाषा को समझते, तस्वीरों को पहचानते और भविष्यवाणी करते हैं। आज एआई केवल सुविधा नहीं, बल्कि विकास का इंजन बन चुका है। दुनिया भर में अनुमान है कि आने वाले वर्षों में एआई वैश्विक अर्थव्यवस्था में खरबों डॉलर का योगदान देगा। उद्योगों में ऑटोमेशन हो या तेज उत्पादन, लागत में कमी हो या बेहतर सेवाएं, एआई लाखों-करोड़ों डेटा का चंद सेकेंड में विश्लेषण कर

आईटी नियमावली, 2021

- आईटी नियमावली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कानूनी दायित्व सौंपे गए हैं। इसमें गलत सूचना, झूठी सूचना और डीपफेक को हटाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई शामिल है।
- कानूनी दायित्वों का पालन करने में मध्यस्थों की विफलता की स्थिति में, मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।
- मध्यस्थों द्वारा शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पीड़ित को प्रभावित करने वाली विकृत या कृत्रिम रूप से उत्पन्न छवियों से संबंधित किसी भी शिकायत का निराकरण करने के लिए 24 घंटे की समय सीमा का प्रावधान किया गया है।

गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक समर्पित पोर्टल [cybercrime.gov.in] लॉन्च किया है। टोल-फ्री नंबर 1930 पर भी कॉल किया जा सकता है। भारत कानूनी सुरक्षा उपायों को तकनीकी समाधानों के साथ जोड़ रहा है। डीपफेक का पता लगाने, गोपनीयता बढ़ाने और साइबर सुरक्षा के लिए एआई उपकरण बनाने के लिए आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

सुरक्षित-विश्वसनीय एआई में आगे के कदम...

- एआई संरक्षा, सुरक्षा और विविध हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट काम कर रहा है।
- शिक्षा जगत, स्टार्टअप, उद्योग जगत और सरकारी निकायों सहित स्टेकहोल्डर हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं।
- जिम्मेदार एआई के इर्द-गिर्द उपकरण और ढांचे बनाए जा रहे हैं, जिनका ध्यान 10 विषयों पर केंद्रित है।
- मशीन अनलर्निंग, एआई पूर्वाग्रह शमन, गोपनीयता बढ़ाने वाले उपकरण, एआई गवर्नेंस परीक्षण आदि को कवर करने वाली 8 जिम्मेदार एआई परियोजनाएं चल रही हैं।
- वॉटरमार्किंग, सैद्धांतिक एआई, जोखिम मूल्यांकन, तनाव परीक्षण और डीपफेक डिटेक्शन टूल जैसे प्रमुख विषयों पर कुछ और परियोजनाओं का भी मूल्यांकन किया जा रहा है।

एआई के चार उत्कृष्टता केंद्र

भारत में एआई विकसित करने और एआई के माध्यम से देश हित में काम करने के उद्देश्य से, वित्त वर्ष 2023-24 की घोषणा के बाद भारत सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, आईआईटी कानपुर और आईआईटी रोपड़ में एआई के तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। इन तीनों केंद्रों के लिए कुल 990 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके बाद 2025-26 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार 500 करोड़ रुपये की लागत से आईआईटी मद्रास में भी एआई का एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।

देता है। इससे जीवन की सुगमता में सुधार होता है। अस्पताल में रोगों की पहचान हो या किसानों को मिलने वाली मौसम की सटीक जानकारी, छात्रों के लिए शिक्षा को समझने की सहजता, एआई इन सबको आसान बनाता है। दुनिया के बड़े देश इसमें बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। टेक कंपनियां एआई के बड़े मॉडल बना रही हैं। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डेटा विश्लेषण में तेजी, रक्षा-साइबर सुरक्षा में एआई का उपयोग, यह स्पष्ट है कि जो देश एआई में आगे होगा, वही भविष्य में अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगा। भारत आज जी-20 जैसे वैश्विक मंचों पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई के मुद्दे उठा रहा है। भारत की सोच साफ है कि एआई कुछ देशों का विशेषाधिकार न बने। यह विकासशील देशों के लिए भी अवसर बने। वर्तमान दशक को भारत टेकेड के रूप में देखता है। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कुछ कर रहा है, वो इक्कीसवीं सदी के सामर्थ्य का आधार बनेगा। चाहे ग्रीन

एआई-आधारित स्टार्टअप को सहायता

- देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े 100 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है।
- स्टेशन एफ और एचईसी पेरिस के साथ इंडियाएआई स्टार्टअप ग्लोबल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि 10 भारतीय एआई स्टार्टअप को यूरोप में अपना विस्तार करने में मदद मिल सके।
- जिम्मेदार एआई और साइबर सुरक्षा में एआई जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले यह स्टार्टअप वर्तमान में स्टेशन एफ में प्रशिक्षण ले रहे हैं।
- प्रशिक्षण लेने वाले स्टार्टअप में कुछ गोपनीयता बढ़ाने वाले एआई और सिक्योर ब्लिंक एआई-संचालित साइबर सुरक्षा, निगरानी, एआई के उपयोग से पृथ्वी के अवलोकन, औद्योगिक निरीक्षण के लिए एआई पर केंद्रित हैं।

युवा शक्ति और एआई... शिक्षण और प्रशिक्षण का इकोसिस्टम

भारत की 65 फीसदी से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष के कम आयु की है। भारत की डिजिटल और इनोवेशन रणनीति के केंद्र में भी यही युवा हैं। भारत एआई को युवाओं के रोजगार और कौशल को बढ़ाने के लिए एक आवश्यक माध्यम मानता है। इसी दृष्टि से भारत सरकार विद्यालय शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, अनुसंधान फेलोशिप और उद्योग जगत के साथ काम करके एक बड़ी एआई प्रतिभा संपन्न श्रृंखला तैयार कर रही है ताकि एआई शिक्षा और कौशल को दी जा सके नई गति...

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल और नए अवसर

- विश्व बैंक की दक्षिण एशिया विकास रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में एआई से संबंधित नौकरी के सबसे अधिक अवसर भारत में हैं। वर्ष 2025 में व्हाइट-कॉलर नौकरियों में 5.8% लिस्टिंग में एआई विशेषज्ञता की आवश्यकता थी, जिसमें बेंगलुरु (एआई नौकरियों का 11% हिस्सा) और हैदराबाद (9.57%), महाराष्ट्र में पुणे (6.95%) और चेन्नई (6.62%) का नंबर आता है।
- एआई से जुड़े रोजगार में वेतन वृद्धि भी अधिक मिल रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल कौशल वाली नौकरियों में औसतन 12% वेतन प्रीमियम मिलता है, जबकि एआई-केंद्रित नौकरियों में यह प्रीमियम 28% तक है।
- जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच, दक्षिण एशिया में एआई से जुड़ी रोजगार पोस्टिंग सभी पदों पर 2.9% से बढ़कर 6.5% हो गई है। इसमें एआई कौशल की मांग गैर-एआई भूमिकाओं के मुकाबले 75% अधिक बढ़ी है।
- स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2025 बताती है कि भारत लगभग 33% की वार्षिक भर्ती दर के साथ एआई प्रतिभा अधिग्रहण में दुनिया में अग्रणी है। इतना ही नहीं एआई कौशल की पहुंच समान व्यवसायों में वैश्विक औसत से 2.5 गुना अधिक है।

एनर्जी हो, चाहे स्पेस टेक हो, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मानवता का भविष्य तय करने वाली हर टेक्नोलॉजी में भारत आज अभूतपूर्व निवेश कर रहा है।

इसी सोच का परिणाम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज भारत की विकास यात्रा का एक केंद्रीय स्तंभ बन गया है। यह सुशासन को सुदृढ़ कर रहा है, सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में

> *मानव इतिहास में हर कुछ शताब्दियों के बाद एक टर्निंग प्वाइंट आता है, और वो टर्निंग प्वाइंट सभ्यता की दिशा रिसेट करता है। वहीं से विकास की रफ्तार बदलती है, सोचने, समझने और काम करने के पैराडाइम्स बदलते हैं।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

सुधार ला रहा है और ऐसे समाधानों को सक्षम बना रहा है जो व्यापक स्तर पर नागरिकों तक पहुंच सकें। मानव प्रगति को हमेशा तकनीक ने आकार दिया है। बिजली ने दैनिक जीवन और कार्यशैली को बदला, कंप्यूटर ने सूचनाओं के प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के तरीके को बदल दिया, इंटरनेट ने सीमाओं के पार लोगों और प्रणालियों को जोड़ा और मोबाइल फोन ने तकनीक को सीधे नागरिकों के हाथों में पहुंचा दिया। एआई इन्हीं आधारों पर निर्मित हुआ है और अब कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, जलवायु संरक्षण और गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों को बदलने के लिए मनुष्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत के लिए, एआई सबकी पहुंच में हो यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि इसके लाभ व्यापक रूप से साझा किए जाएं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

एआई के दौर में भारत की युवा शक्ति

किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए, ये जरूरी है कि युवाओं को भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश की शिक्षा प्रणाली की भी होती है। इसीलिए भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बनाया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लाई गई, जिसे वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वह एआई आधारित है। आज भारत एआई के विकास और उसे अपनाने में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके

भारत की सुपर कंप्यूटर क्षमता... ताकि एआई दे जल्द समाधान

- भारत में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत अब तक 39 पेटाफ्लॉप्स की संयुक्त क्षमता वाले 37 सुपर कंप्यूटर बनाए और चालू किए गए हैं।
- यह सुपर कंप्यूटर देशभर के शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान और विकास लैब में लगे हैं।
- 10 और सुपर कंप्यूटर चालू करने पर काम जारी। जिसमें 20 पेटाफ्लॉप्स क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा एचपीसी और एआई सेटअप वाला राष्ट्रीय सुविधा केंद्र शामिल है।
- आत्मनिर्भरता के लिए सर्वर, हाईस्पीड इंटरकनेक्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टैक, डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न स्वदेशी उप घटक विकसित किए गए हैं।
- स्वदेशी परम रुद्र सुपर कंप्यूटर स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक और देश में डिजाइन, विकसित और निर्मित रुद्र सीरिज सर्वरों का उपयोग करके बनाए गए हैं।

6,000

रुद्र सर्वर लगाए जा चुके हैं परम रुद्र सपुर कंप्यूटर में, साथ ही 1,500 और सर्वर बनाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन लांच किया है। इससे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई-क्वालिटी डेटा सेट्स और रिसर्च फैसिलिटी तैयार की जा रही हैं। भारत में एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। देश के जाने-माने संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप के द्वारा इन सेंटर्स को गति मिल रही है। भारत मेक इन इंडिया के विजन पर काम कर रहा है और इस क्षेत्र में भी विजन है- मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। तकनीक की इस यात्रा को समय से पूरा करने और भविष्य की तकनीक में भारत को 'बेस्ट इन वर्ल्ड' की लिस्ट में शामिल करने की दिशा में काम हो रहा है। भारत सार्वजनिक हित के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोग विकसित कर रहा है। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। भारत अपनी विविधता को देखते हुए अपना स्वयं का बड़ा भाषा मॉडल बना रहा है। भारत यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए तैयार है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य अच्छे के लिए और सभी के लिए हो।

भारत की तैयारी: मजबूत डिजिटल नींव

भारत ने एआई की दिशा में अचानक कदम नहीं बढ़ाया। बीते एक दशक से अधिक समय में अपना डिजिटल आधार तैयार किया है। डिजिटल इंडिया मिशन ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया, इंटरनेट को सुलभ बनाया और डिजिटल सशक्तीकरण की नींव रखी। इसमें आधार और डिजिटल पहचान ने हर नागरिक को एक डिजिटल पहचान दी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को आसान बना दिया। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी तक इसका उपयोग कर रहे हैं। कोविन

प्लेटफॉर्म ने कोविड के समय करोड़ों टीकाकरण का डिजिटल रूप से प्रबंधन किया। यह दुनिया के सामने भारत की तकनीकी क्षमता का उदाहरण बना। इन सभी पहलों ने डेटा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी आत्मविश्वास दिया, जो एआई के लिए जरूरी था। सरकार ने "इंडिया एआई मिशन" के माध्यम से एआई रिसर्च, स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े निवेश की घोषणा की। कौशल विकास में इसे शामिल किया, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया, भारत की विविध भाषाओं को ध्यान में रखते हुए एआई मॉडल विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि तकनीक केवल अंग्रेजी तक सीमित न रहे। भारत सरकार जिम्मेदार और नैतिक एआई पर बल दे रही है। इसमें डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा शामिल है। विज्ञान और तकनीक की परिवर्तनकारी शक्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे नैतिक और समावेशी बनाना चाहिए। आज रीटेल से लॉजिस्टिक्स तक, उपभोक्ता सेवा से लेकर बच्चों के होमवर्क तक, हर जगह एआई का प्रयोग हो रहा है। इसलिए भारत में भी एआई की शक्ति को समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है।

> *एआई इंपैक्ट समिट 2026 में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली हैं। इस दौरान भारत ने तीन मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। यह अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही है।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

एआई न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकता है, बल्कि सभी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी समान भागीदार बना रहा है। डेटा एनालिटिक्स की मदद से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। एआई संचालित डेटा वेरिफिकेशन के जरिए फर्जी लाभार्थियों की पहचान से हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। एआई के उपयोग को लेकर 2018 में ही भारत ने 'नेशनल स्ट्रैटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' की शुरुआत की थी। जिसका उद्देश्य कुछ खास क्षेत्रों में एआई के विकास को बढ़ावा देना था। वर्ष 2021

में 'रिस्पांसिबल एआई' पर एक ड्राफ्ट पेश किया गया, जिसमें नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दिया गया। इस नेशनल स्ट्रैटजी को 'एआई फॉर ऑल' की थीम पर तैयार किया गया। बीते वर्ष ही प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'मेकिंग एआई इन इंडिया' और 'मेकिंग एआई वर्क इन इंडिया' के विजन पर चलते हुए 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजट प्रावधान के साथ राष्ट्रीय स्तर के इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी। यह मिशन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारियों के माध्यम से एआई इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला एक वृहद इकोसिस्टम स्थापित करेगा। वर्ष 2025 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस की सह अध्यक्षता में आयोजित पेरिस एआई शिखर सम्मेलन में एआई को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया था, ताकि यह सभी वर्गों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इसी संदर्भ में एआई महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक हिंसा की रोकथाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एआई आधारित आपातकालीन अलर्ट सिस्टम महिलाओं को तुरंत मदद में सहायता प्रदान कर सकता है। विकसित भारत 2047 के विजन के तहत भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उसमें यह तकनीक निर्णायक भूमिका निभाएगा। यह तकनीक एक समावेशी और प्रगतिशील समाज की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

भारत की एआई यात्रा सिर्फ कोड और एल्गोरिद्म की कहानी नहीं है। यह उस सोच की कहानी है जिसमें तकनीक को मनुष्य का साथी माना गया है। आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में उस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है जो मानवता की दिशा को आकार देगा। कुछ लोगों को बुद्धिमत्ता में मशीनों को इंसानों से बेहतर होने की चिंता है। लेकिन सामूहिक भविष्य और साझा नियति की कुंजी मानव के अलावा किसी और के पास नहीं है। इसलिए एआई कोई जादू नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए भारत का संदेश साफ है कि "एआई का भविष्य तभी उज्ज्वल है जब वह मानवता के साथ चले।"

निश्चित रूप से एआई के साथ हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का विस्तार टेक्नोलॉजी के एक उपकरण से भी कहीं ज्यादा है। एआई नए भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रही है। एआई की एक बहुत बड़ी ताकत है, लोगों को जोड़ने की। एआई के सही इस्तेमाल से सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति ही सुनिश्चित नहीं होती बल्कि ये समानता और सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल बुनियाद मजबूत की, एआई मिशन की शुरुआत की और दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि एआई का भविष्य मानवता के साथ है, मानवता के बिना नहीं। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 इसी विश्वास का उत्सव बना है। ■

सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक

'केरल' होगा अब 'केरलम'

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बनेगा सिविल एन्क्लेव

युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, 24 फरवरी के दिन नवनिर्मित सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक हुई। इसमें देश के लिए कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए। इस दौरान, मंत्रिमंडल ने यह संकल्प भी लिया कि स्वदेशी सोच, आधुनिक स्वरूप और 140 करोड़ देशवासियों के अनंत सामर्थ्य की बुनियाद पर बना सेवा तीर्थ राष्ट्र सेवा के कर्तव्य-यज्ञ को निरंतर बढ़ाएगा आगे...

कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

निर्णय : 'केरल' राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

प्रभाव : केंद्रीय मंत्रिमंडल से स्वीकृत इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्वारा केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल राज्य विधानसभा को संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत विचार-विमर्श हेतु भेजा जाएगा। केरल राज्य विधानसभा की राय प्राप्त होने के बाद, भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

निर्णय : श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्तावित 1,677 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सिविल एन्क्लेव के विकास को मंजूरी।

प्रभाव : यह कश्मीर घाटी में विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 73.18 एकड़ में फैले नई सिविल एन्क्लेव परियोजना में 71,500 वर्ग मीटर में फैला एक अत्याधुनिक टर्मिनल भवन होगा, जिसे व्यस्ततम समय में 2,900 यात्रियों की सेवा और प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। इसके तहत सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरकों का निर्माण भी शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के अतिरिक्त, इस परियोजना से डल झील, शंकराचार्य मंदिर और मुगल गार्डन जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों से बेहतर संपर्क स्थापित कर पर्यटन और आर्थिक विकास को उल्लेखनीय रूप से प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। श्रीनगर एक प्रमुख पर्यटन और आर्थिक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करेगा।

निर्णय : 2026-27 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी।

प्रभाव : कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) का एमएसपी 5,925 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इससे जूट के अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत पर 61.8 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित होगा। 2026-27 के लिए कच्चे जूट का एमएसपी पिछले मार्केटिंग सीजन 2025-26 की तुलना में 275 रुपये प्रति क्विंटल अधिक

है। भारतीय जूट निगम मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखेगी और ऐसे संचालन में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई पूरी तरह से केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी।

निर्णय : महारत्न सीपीएसई पर लागू शक्तियों के डेलिगेशन संबंधी लोक उद्यम विभाग के 4 फरवरी, 2010 के दिशा-निर्देशों के तहत पावर ग्रिड को अधिक शक्तियां सौंपने की मंजूरी।

प्रभाव : इस मंजूरी से पावरग्रिड की प्रति सहायक कंपनी इक्विटी निवेश की सीमा वर्तमान 5,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,500 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि कंपनी की कुल संपत्ति के 15 प्रतिशत की मौजूदा सीमा बरकरार रखी गई है। इस मंजूरी से देश के सबसे बड़े और सबसे अनुभवी ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता, पावर ग्रिड को अपने मुख्य व्यवसाय में निवेश बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे गैर-जीवाश्म-आधारित स्रोतों से 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

निर्णय : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के 8 जिलों में रेलवे लाइनों की संख्या बढ़ाने संबंधी तीन मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी।

प्रभाव : भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की वृद्धि होगी। प्रस्तावित मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 5,407 गांवों में संपर्क में सुधार होगा, जिनकी आबादी लगभग 98 लाख है। कुल 9,072 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ये परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी। बढ़ी हुई रेल लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार आएगा और भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ेगी। इस कार्य के पूरा होने पर परिचालन सुव्यवस्थित बनाने और माल तथा यात्री भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी।

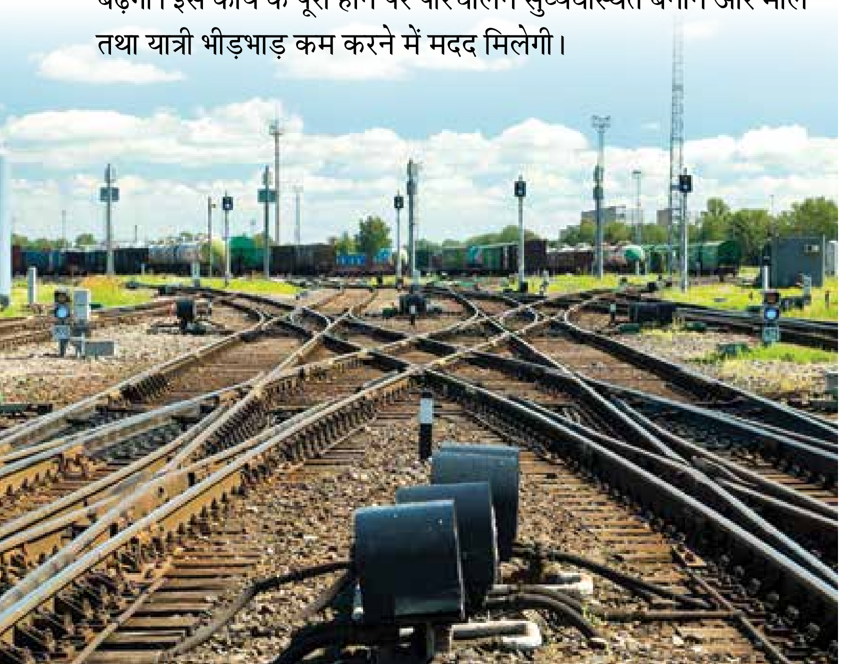

'सेवा तीर्थ' में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक प्रथम बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, नए प्रधानमंत्री कार्यालय 'सेवा तीर्थ' में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक प्रथम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह संकल्प दोहराया कि यहां लिया गया हर निर्णय 140 करोड़ देशवासियों के प्रति सेवा-भाव से प्रेरित होगा और राष्ट्र-निर्माण के व्यापक लक्ष्य से जुड़ा होगा। इस परिसर में लिया गया प्रत्येक निर्णय 'नागरिक देवो भव' की भावना से प्रेरित होगा। यह स्थान सत्ता के प्रदर्शन का नहीं बल्कि प्रत्येक भारतवासी के सशक्तीकरण का केंद्र बनेगा। 'सेवा तीर्थ' से संचालित शासन का हर प्रयास देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने की भावना से जुड़ा रहेगा।

निर्णय : गुजरात मेट्रो रेल निगम लि. के अंतर्गत जीआईएफटी सिटी से शाहपुर तक वर्तमान उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के विस्तार को स्वीकृति।

प्रभाव : यह कॉरिडोर 3.33 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें तीन एलिवेटेड स्टेशन होंगे। यह परियोजना लगभग चार वर्षों में पूरी होने वाली है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,067.35 करोड़ रुपये है। इस विस्तारित कॉरिडोर से 2029 में लगभग 23,702 यात्रियों और 2041 में लगभग 58,059 यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह कॉरिडोर अहमदाबाद और जीआईएफटी क्षेत्र के बीच संपर्क को मजबूत करेगा। प्रस्तावित मार्ग पर स्थित प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और वाणिज्यिक केंद्रों को इससे सीधे लाभ मिलेगा। ▪

चिप निर्माण में भारत बनेगा आत्मनिर्भर

विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है, जब भारत आत्मनिर्भर होगा और इसके लिए मेड इन इंडिया चिप का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब चिप मेड इन इंडिया होगी तो हमें आधुनिक साजो-सामान की मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। यही कारण है कि 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश में एचसीएल-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट के भूमिपूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं 28 फरवरी को उन्होंने गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग केंद्र का भी किया उद्घाटन...

भारत, आज विकसित होने के लक्ष्य पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो काम कर रहा है, वही इक्कीसवीं सदी में देश की ताकत और तरक्की की मजबूत नींव बनेगा। ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक, डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानवता का भविष्य तय करने वाली हर टेक्नोलॉजी में भारत अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में एचसीएल-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत ने अपना सफर भले ही देरी से शुरु किया हो लेकिन अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत ने अपने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, अभी तक 10 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। इनमें से चार यूनिट में बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरु होने वाला है।

सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होता है। ये इकोसिस्टम, मशीन बनाने वाले, डिजाइन इंजीनियर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और कुशल टेक्नीशियन जैसे अनेक लेयर्स से मिलाकर बनता है। सबके तालमेल से एक चिप तैयार होती है। भारत भी, सेमीकंडक्टर

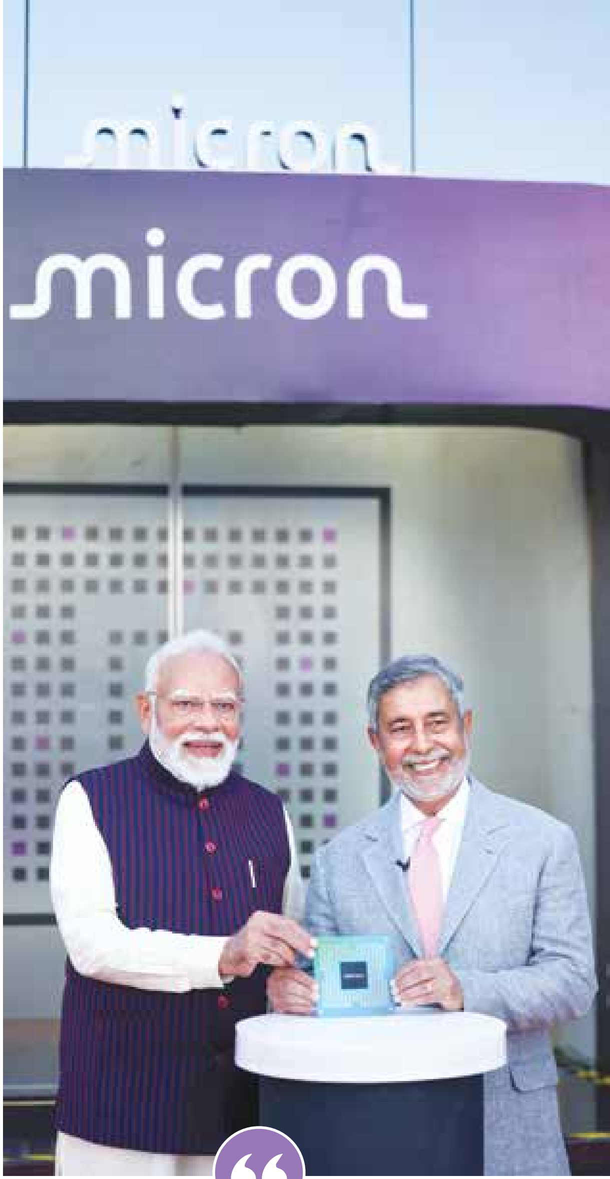

> अभी तक सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत कुल 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से माइक्रोन के अलावा, तीन और प्रोजेक्ट्स भी बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरु करने वाले हैं। हम जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं वो पैन इंडिया है। यानी विकसित भारत के नए टेक हब्स देश के हर हिस्से में विकसित किए जा रहे हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

एचसीएल-फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना-इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड का शिलान्यास

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में एचसीएल-फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना-इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड का शिलान्यास किया।
- एचसीएल-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी की स्थापना भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
- इस परियोजना के माध्यम से भारत को हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए एक विश्वसनीय ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

परियोजना पर 3,700 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

- 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश वाली यह परियोजना घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और मजबूत ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने में मदद करेगी।
- यह मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, ऑटोमोटिव, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपकरणों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- इस पहल के माध्यम से भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा।
- इंजीनियर, टेक्नीशियन और प्रोफेशनल्स के लिए हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। साथ ही यह सहायक उद्योगों में विकास को भी गति प्रदान करेगी।
- यह परियोजना एक मजबूत व आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम को बनाने की दिशा में बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले एटीएमपी का गुजरात में उद्घाटन

- साणंद एटीएमपी संयंत्र से भारत में निर्मित पहले सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का वाणिज्यिक उत्पादन और शिपमेंट शुरू हो गया है। यह विकास वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- साणंद की इस परियोजना का शिलान्यास सितंबर 2023 में हुआ था और यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत स्वीकृत होने वाला पहला प्रस्ताव था।
- इसे 22,500 करोड़ रुपये से अधिक के कुल खर्च के साथ, निर्माण कार्य स्वीकृति के तुरंत बाद शुरू किया गया। इससे देश में रणनीतिक सेमीकंडक्टर निवेश को गति देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है।
- साणंद संयंत्र पूरी तरह से चालू हो जाने पर लगभग 5 लाख वर्ग फुट का क्लीनरूम क्षेत्र उपलब्ध होगा और यहां दुनिया के सबसे बड़े रेज्ड-फ्लोर क्लीनरूम में से एक बन जाएगा।

इकोसिस्टम की पूरी वैल्यू चेन पर फोकस कर रहा है। गुजरात के साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुविधा के उद्घाटन अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। इसका मकसद है कि जैसे-जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे-वैसे भारत में ही घटकों और सामग्री की मांग बढ़ेगी।

तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिली 7,100 करोड़ रुपये की परियोजनाएं

मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर... जीवन होगा और बेहतर

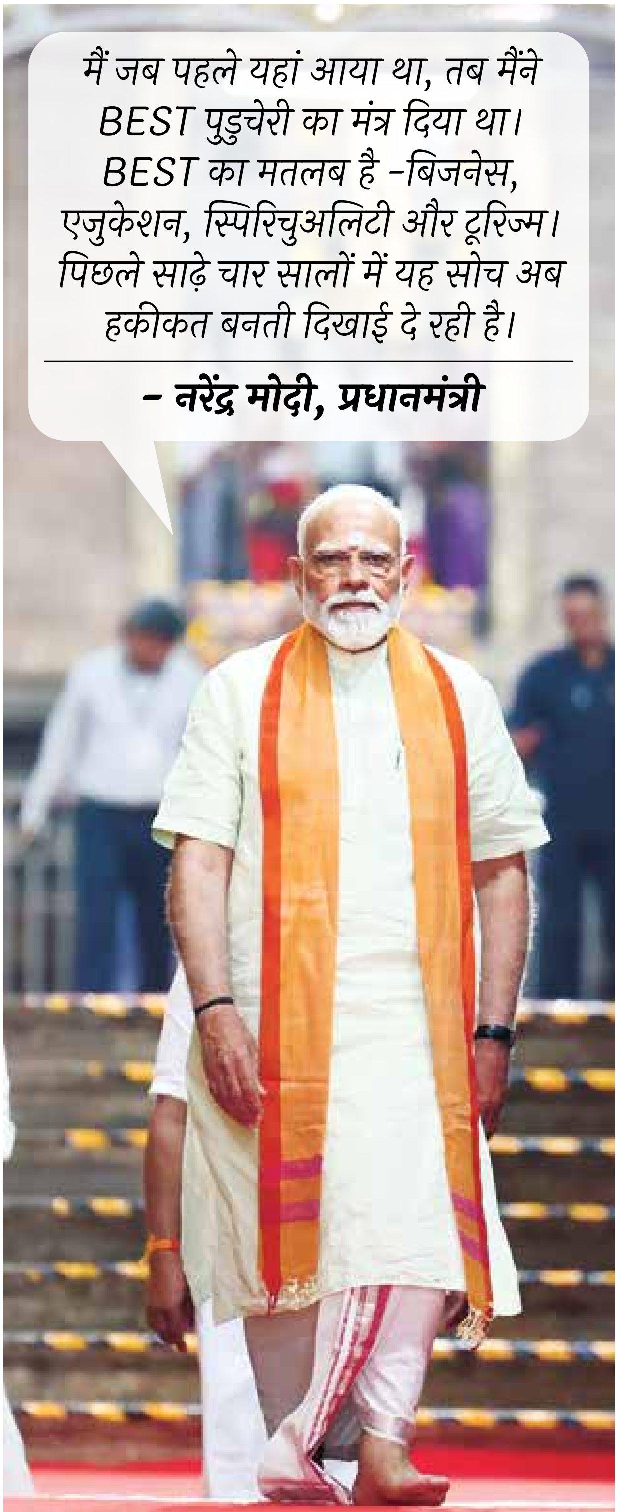

मैं जब पहले यहां आया था, तब मैंने BEST पुडुचेरी का मंत्र दिया था। BEST का मतलब है -बिजनेस, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और टूरिज्म। पिछले साढ़े चार सालों में यह सोच अब हकीकत बनती दिखाई दे रही है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

मजबूत और सशक्त युवा, स्वस्थ मानव शक्ति, परिवहन-संपर्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण सारथी होता है। भारत सरकार अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार निर्माण कर रही है। वित्त वर्ष 2026-27 में इंफ्रा पर 12 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अधिक धन... मतलब, लोगों का जीवन और आसान बनाने वाली सड़कें, जल आपूर्ति, तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल और अस्पताल का निर्माण। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को मदुरै में 4,400 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 2,700 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास...

राष्ट्र को विकसित भारत की संकल्प सिद्धि के लिए तैयार करने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को तमिलनाडु के मदुरै में 4,400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं पुडुचेरी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, औद्योगिक प्रगति, शिक्षा, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा और सस्टेनेबल ग्रोथ को गति देने वाली विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की, कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरै और पुडुचेरी में जनसभा को भी संबोधित किया। वहां उन्होंने कहा कि मदुरै में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और पूरे तमिलनाडु के लोगों को महत्वपूर्ण लाभ होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरै के कार्यक्रम में कहा कि हाई-क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण लोगों के सशक्तीकरण का माध्यम है। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के हाईवे पर भारी निवेश किया है, जिससे तीर्थ यात्रियों की यात्रा बेहतर हुई है। कृषि और समुद्री उत्पादों की ढुलाई आसान हुई है। पिछले दस सालों में भारतीय रेल एक आधुनिक, कुशल और जन केंद्रित परिवहन व्यवस्था में बदल गई है।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

पुडुचेरी में उद्घाटन और शिलान्यास वाली प्रमुख परियोजनाएं

- पीएम ई-बस सेवा के तहत ई-बसों का परिचालन का शुभारंभ।
- पुडुचेरी सरकार की सीवरेज और जलापूर्ति क्षेत्र की योजनाओं का उद्घाटन।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कराईकल के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग ब्लॉक और गंगा हॉस्टल, जेआईपीएमईआर में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के आधुनिकीकरण तथा पुडुचेरी विश्वविद्यालय के नए भवनों व छात्रावास का लोकार्पण।
- 750 एकड़ में फैला करासूर-सेदरापेट औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 41 ग्रामीण सड़कों के निर्माण, पुडुचेरी में हेरिटेज टाउन के विकास और मिष्टी योजना के अंतर्गत मैंग्रोव संरक्षण कार्यों का शिलान्यास।

एसएएससीआई योजना में पुडुचेरी शामिल

राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई-स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट) के तहत शहरी सड़कों, जल निकासी नेटवर्क, सार्वजनिक भवनों, छात्रावास और खेल सुविधाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। भारत सरकार ने पुडुचेरी को एसएएससीआई योजना में शामिल करने की मंजूरी दी है, जो मूल रूप से केवल राज्यों तक ही सीमित थी।

तमिलनाडु में तेज हुआ विकास

- वर्ष 2014 से अब तक तमिलनाडु में 4,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया गया है।
- पिछले दशक की तुलना में तमिलनाडु के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण में तीन गुना वृद्धि हुई है। वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से रेलवे बजट में लगभग नौ गुना की वृद्धि।
- 2009 से 2014 के बीच वार्षिक बजट आवंटन 880 करोड़ रु. था, वहीं वर्ष 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर 7,600 करोड़ रु. कर दिया गया है।
- राज्य में 1,300 किमी से अधिक की नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं, 97 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।
- नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ जो भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है।
- वर्तमान में 9 वंदे भारत और 9 अमृत भारत ट्रेनें तमिलनाडु के लोगों की सेवा कर रही हैं, जिनके कोच चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईएफसी) में निर्मित किए गए हैं।
- अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 77 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

तमिलनाडु में प्रमुख परियोजनाएं

- एनएच-332ए के मरक्कनम-पुडुचेरी सेक्शन और एनएच-87 के परमकुडी-रामनाथपुरम सेक्शन को फोर-लेन (चार-लेन) बनाने की आधारशिला।
- अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 8 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन जिसमें मोराप्पुर, बोम्मिडी, श्रीविल्लीपुत्तुर, शोलावंदन, मनापराई, पोलाची जंक्शन, कराईकुडी जंक्शन, तिरुवरूर जंक्शन शामिल हैं।
- चेन्नई बीच-चेन्नई एग्मोर चौथी लाइन राष्ट्र को समर्पित।
- कुंभकोणम, येरकॉड और वेल्लोर में तीन नए आकाशवाणी एफएम रिले ट्रांसमीटरों का उद्घाटन।

वित्त वर्ष 2026-27 में बेंगलुरु-चेन्नई और चेन्नई-हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रस्ताव है। तमिलनाडु को रेयर अर्थ कॉरिडोर का हिस्सा बनाया गया है, जिसका उद्देश्य उन्नत विनिर्माण, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय बजट में तमिलनाडु को रेयर अर्थ कॉरिडोर का हिस्सा बनाया गया है जो उन्नत विनिर्माण, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देता है। विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए तमिलनाडु का विकास सरकार का सामूहिक लक्ष्य है। ■

नमो भारत का विस्तार सुगम यात्रा, समृद्धि अपार

केंद्र सरकार देशवासियों को हाईस्पीड देना चाहती है, जाम और प्रदूषण से मुक्त कर हर प्रकार की सुविधा देना चाहती है। इसलिए, आज देश में नमो भारत जैसी आधुनिक सेमी-हाईस्पीड ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन चल रही है। बीते 11 वर्षों में देश के दर्जनों शहरों तक मेट्रो पहुंची है। सुविधा मुहैया कराने की इसी कड़ी में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी को मेरठ की धरती पर एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का किया शुभारंभ...

भारत में 2014 से पहले मेट्रो का विस्तार, बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। हालत यह थी कि उस समय देश के सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई थी। जबकि आज देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगी है और दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में विभिन्न विकास कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में पहली बार हो रहा है, जब एक ही स्टेशन, एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो रेल दौड़ेगी। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से आप शहर के भीतर भी यात्रा कर पाएंगे और उसी स्टेशन से सीधे दिल्ली भी आ-जा सकते हैं।

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितने रुपये खर्च हो रहे हैं, उससे लोगों का पैसा भी बचता है और युवाओं को रोजगार भी मिलता है। पश्चिम यूपी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहां नए-नए एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट जब बनते हैं तब रोजगार भी मिलते हैं और बाद में

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहां से उन्होंने मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो का सफर किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल-कॉलेज के अनेक युवाओं और अन्य यात्रियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में लगभग 12,930 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजनाएं शहरी गतिशीलता को बदलेंगी और नागरिकों के जीवन को सहज बनाएगी।

हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए, उसे पूरा करने के लिए दिन-रात एक कर दिया जाए। और इसलिए अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती, भटकती नहीं हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित

82 किलोमीटर लंबा दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया।

- भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के शेष खंडों का भी उद्घाटन। इनमें दिल्ली में सराय काले खान और न्यू अशोक नगर के बीच का 5 किलोमीटर का खंड और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच का 21 किलोमीटर का खंड शामिल है।
- 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ, नमो भारत देश की पहली क्षेत्रीय तीव्र ट्रांजिट सिस्टम है।
- नमो भारत से साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्र दिल्ली से अधिक तेजी से जुड़ पाएंगे।
- कॉरिडोर का दिल्ली में शुरुआती स्टेशन सराय काले खां, शुरू होने वाले 4 नमो भारत स्टेशनों में से एक है।
- यह रणनीतिक रूप से एक प्रमुख मल्टी-मॉडल हब के रूप में स्थित है जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, वीर हकीकत राय आईएसबीटी और रिंग रोड को सरलता से जोड़ता है।
- शुरू होने वाले अन्य तीन नमो भारत स्टेशन शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम मेरठ में हैं।

मेरठ दक्षिण और मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो सेवा का उद्घाटन

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ दक्षिण और मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो सेवा का भी उद्घाटन किया जो नमो भारत के ही बुनियादी ढांचे पर संचालित होगी।
- यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है। मेरठ मेट्रो भारत की सबसे तेज मेट्रो प्रणाली होगी, जिसकी अधिकतम परिचालन गति लगभग 120 किमी प्रति घंटा होगी।
- मेट्रो सभी निर्धारित पड़ावों सहित पूरी दूरी मात्र 30 मिनट में तय करेगी।
- एक ही बुनियादी ढांचे पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो, तेज रफ्तार वाली अंतर-शहरी यात्रा और शहर के भीतर सुगम आवागमन के लिए मददगार साबित होगा। शहरी और क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करेगा।
- सड़क यातायात में भीड़ कम होगी। इससे वाहनों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी।

नए उद्योग लगते हैं, उससे भी रोजगार सृजन होता है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की यह धरती श्रम और सृजन की धरती है। यहां के किसान, पशुपालक, छोटे-लघु उद्यमी, बुनकर-शिल्पकार, सभी विरासत और विकास के मंत्र को साकार कर रहे हैं। ऐसे में जब भारत का सामर्थ्य बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश के इन सभी साथियों को भी फायदा होता है।

बजट वेबिनार

बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण

हर साल बजट के बाद होने वाले वेबिनार केवल विचारों के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं हैं बल्कि एक प्रभावी विचार-मंथन का मंच बन गया है। यह लोगों के अनुभव और व्यावहारिक चुनौतियों पर आधारित सुझाव, आर्थिक रणनीतियों को बेहतर बनाने और समाधान खोजने में मदद कर रहा है। "विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त" और "सतत और सशक्त आर्थिक विकास" विषय पर क्रमश: 27 फरवरी और 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट वेबिनार को किया संबोधित...

भारत ने पिछले एक दशक में असाधारण लचीलापन दिखाया है। यह संयोग नहीं है। यह लचीलापन, दृढ़ विश्वास से प्रेरित सुधार की देन है। सरकार ने प्रक्रिया को सरल किया है और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है। टेक्नोलॉजी प्रेरित शासन का विस्तार किया है, संस्थानों को मजबूत किया है और आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। "विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त" विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस गति को बनाए रखने के लिए न केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है, बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। रिफॉर्म का मूल्यांकन घोषणा से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव से होना चाहिए। एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग कर पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ानी ही होगी। साथ ही शिकायत निवारण प्रणालियों से इंपैक्ट की निरंतर निगरानी भी करनी होगी।

पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस रहा है। सरकार ने सोच-समझकर फैसला किया कि भारत का विकास हाईवे, रेलवेज, बंदरगाह, डिजिटल नेटवर्क, पावर सिस्टम जैसी अनेक ठोस परिसंपत्तियों को तैयार करने से ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं सभी स्टेकहोल्डर्स, फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन्स, मार्केट्स, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल्स और इनोवेटर्स से कहूंगा कि इस बजट ने जो नए अवसर दिए हैं, उनका फायदा उठाएं, बजट द्वारा खोले गए नए अवसरों के साथ गहराई से

बजट के बाद होने वाले वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण

अक्सर बजट का आकलन अलग-अलग पैरामीटर पर किया जाता है। कभी स्टॉक मार्केट की चाल पर बात होती है तो कभी आयकर प्रस्तावों पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। सच्चाई यह है कि बजट कोई अल्पकालिक व्यापार दस्तावेज नहीं होता, वह एक पॉलिसी रोडमैप होता है। इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करे, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाए, जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाए। बजट में इससे जुड़े निर्णय ही अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती देते हैं। हर बजट एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है और देश के सामने वो बड़ा लक्ष्य है, साल 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। हर रिफॉर्म, हर आवंटन, हर बदलाव को इस लंबी यात्रा के हिस्से के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

बजट के बाद आयोजित वेबिनार की कुछ खास बातें...

- वेबिनार में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र की संरचना को सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई।
- पूंजी बाजारों को मजबूत बनाने तथा कर सुधारों के माध्यम से नागरिकों के जीवन यापन को अधिक सरल और सुगम बनाने पर व्यापक चर्चा हुई।
- वेबिनार का उद्देश्य पिछले अनुभवों से सीख लेना और इसमें शामिल लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना है ताकि बजट घोषणाओं को मजबूती से क्रियान्वित किया जा सके।
- वेबिनार में उद्योग, वित्तीय संस्थानों, बाजार प्रतिभागियों, सरकार, उद्योग नियामकों और शिक्षा जगत के हितधारकों को एक साथ लाया गया ताकि प्रमुख बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन मार्गों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

हम विदेशी इन्वेस्ट फ्रेमवर्क को और सरल कर रहे हैं। हमारा प्रयास सिस्टम को ज्यादा प्रेडिक्टेबल और इन्वेस्टर-फ्रेंडली बनाने का है। हम लॉन्ग-टर्म फाइनेंस को बेहतर बनाने के लिए, बॉन्ड मार्केट को और ज्यादा सक्रिय बनाने की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

27 फरवरी के बजट वेबिनार में

भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। हमारे लिए अवसरों का बहुत बड़ा द्वार खुला है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्वालिटी पर कभी भी समझौता न करें।

– नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री

3 मार्च के बजट वेबिनार में

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

जुड़ें। आपकी भागीदारी से योजनाओं का कार्यान्वयन और बेहतर होगा। साथ ही आपके फीडबैक और सहयोग से बेहतर नतीजे आएंगे। आइए, हम सब मिलकर रिफॉर्म करें, ग्रो करें और ऐसा भविष्य बनाएं जिससे विकसित भारत का सपना जल्द से जल्द साकार हो।

वहीं 3 मार्च को 'सतत और सशक्त आर्थिक विकास' विषय पर हुए बजट वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया विश्वसनीय और लचीले मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर की तलाश में है। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाए।

भारत की शक्तिशाली समुद्री क्रांति

भारत का आकार के हिसाब से 95 फीसदी और मूल्य के हिसाब से 70 फीसदी व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। समुद्र भारत के व्यापार की प्राणशक्ति है। इस प्राणशक्ति को मजबूती देने वाले समुद्री अमृत काल विजन 2047 और समुद्री भारत विजन 2030 का प्रमुख स्तंभ है सागरमाला कार्यक्रम। सागरमाला 25 मार्च को अपने 11 वर्ष पूरे कर रहा है जिसमें पूरी हुई हैं 280 परियोजनाएं, पत्तन का विकास और कनेक्टिविटी हुई मजबूत...

आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की सिद्धि के लिए वर्तमान सरकार अनेक कार्यक्रम और पहल कर रही है। भविष्य के लिए तैयार भारत अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर लंबे संभावित नौवहन योग्य जलमार्ग को संभावनाओं के कैनवास में बदल रहा है। वैश्विक समुद्री शक्ति बनने के लिए एक समुद्रीय इकोसिस्टम बनाने पर काम कर रहा है। इसके लिए समुद्री अमृत काल विजन 2047 और समुद्री भारत विजन 2030 पेश किया है ताकि भारत की लॉजिस्टिक लागत कम हो, आर्थिक विकास को मजबूती मिले और रोजगार सृजन से तटीय क्षेत्र के नागरिकों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। इन बड़े लक्ष्यों की नींव में 25 मार्च, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूर सागरमाला की परिकल्पना और संस्थागत ढांचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 में इस क्षेत्र में वैश्विक निवेश को लेकर कहा था, "यह भारत आने का सही समय है। समुद्री मार्ग से आना और बेहतर है। भारतीय जहाज लंबी दौड़ के लिए सुसज्जित हैं। मत खोईए यह अवसर।"

समुद्री विजन 2030 पर आधारित समुद्री अमृत काल विजन 2047 ने 4 मिलियन जीआरटी की जहाज निर्माण क्षमता और प्रतिवर्ष 10 अरब मीट्रिक टन बंदरगाह

सहायता के पांच स्तंभ

पत्तन आधुनिकीकरण

2.91 लाख करोड़ रुपये के 234 प्रोजेक्ट का हो रहा है कार्यांवयन, 103 प्रोजेक्ट पूरे। 230 एमटीपीए की क्षमता जोड़ी गई।

पत्तन कनेक्टिविटी

2.06 लाख करोड़ रुपये के 279 प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर। 1,500 किलोमीटर पत्तन लिंक कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले 92 प्रोजेक्ट पूरे।

पत्तन आधारित औद्योगीकरण

55,000 करोड़ रुपये के 14 प्रोजेक्ट पर काम, 9 प्रोजेक्ट हुए पूरे।

तटीय सामुदायिक विकास

26,000 करोड़ रुपये के 310 से अधिक प्रोजेक्ट। 30,000 से अधिक मछुआरे लाभान्वित, तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ सुधार।

तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग

10,000 करोड़ रुपये 119 प्रोजेक्ट के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित।

सड़क-रेल परियोजनाएं

यूं तो नाम सागरमाला कार्यक्रम है लेकिन इसमें 272 सड़क और रेल संपर्क परियोजनाएं भी चिन्हित की गई हैं। 272 परियोजनाओं में से 74 पूरी हो चुकी हैं, 67 पर काम चल रहा है और 131 अभी अलग-अलग चरण में हैं।

128 परियोजनाओं का वित्त पोषण

सागरमाला में 8,936 करोड़ रुपये की कुल लागत से फरवरी, 2026 तक 128 परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए मंजूरी दी गई है। इनमें से 78 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जबकि 3,581 करोड़ रुपये की 50 परियोजनाएं अलग-अलग स्तर पर कार्यांवयन में हैं।

संचालन का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को शीर्ष 5 जहाज निर्माण करने वाले देशों में स्थान दिलाना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति में सागरमाला कार्यक्रम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 839 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5.79 लाख करोड़ रुपये है। इनमें से 2.42 लाख करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 119 परियोजनाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। सागरमाला कार्यक्रम की 280 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें लगभग 1.42 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। 1.62 लाख करोड़ रुपये की 209 परियोजनाओं का कार्यान्वयन चल रहा है जबकि 2.75 लाख करोड़ रुपये की 350 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

सागरमाला ने भारत के बंदरगाहों की परिचालन गति को बढ़ाया है, तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है और अंतरदेशीय जलमार्गों को पुनर्जीवित किया है। वैश्विक लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में सुधार किया है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि एक दशक में तटीय जहाजरानी में 118% की वृद्धि हुई, रो-पैक्स फेरी ने 40 लाख से अधिक यात्रियों का परिवहन किया। अंतर्देशीय जलमार्गों से माल ढुलाई में 700% की वृद्धि हुई। नौ भारतीय बंदरगाह विश्व के शीर्ष 100 बंदरगाहों में शामिल हैं, जिनमें विशाखापत्तनम शीर्ष 20 कंटेनर बंदरगाहों में से एक है। भारतीय बंदरगाह अब कई प्रमुख मापदंडों पर उन्नत समुद्री देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

सागरमाला इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण भी, रोजगार भी

सागरमाला में शामिल सभी स्तंभ मिलकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, तटीय समुदायों के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन, अंतर्देशीय जल परिवहन एवं निर्यात-आयात व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करते हैं। इससे बहु-आयामी लॉजिस्टिक्स पार्क, जहाज मरम्मत क्लस्टर और हरित हाइड्रोजन ईंधन हब जैसे सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा जिसका अर्थव्यवस्था पर मजबूत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही आजीविका, क्षेत्रीय विकास और समुद्री क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। समुद्री अमृत काल विजन से 2047 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ■

राष्ट्रपति का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जीवन राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक

आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पंच प्राणों की बात कही थी। उनमें से एक है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। यही वजह है कि आज देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़कर भारत की संस्कृति से जुड़ी चीजों को महत्व देने लगा है। इस दिशा में राष्ट्रपति भवन ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और 23 फरवरी को 'राजाजी उत्सव' मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का किया गया अनावरण...

स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उन लोगों में थे, जिन्होंने सत्ता को पद की तरह नहीं, सेवा की तरह देखा। सार्वजनिक जीवन में उनका आचरण, आत्मसंयम और स्वतंत्र चिंतन, आज भी देश को प्रेरित करता है। दुर्भाग्य से, आजादी के बाद भी राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश प्रशासकों की मूर्तियां तो लगी रही लेकिन देश के महान सपूतों को जगह नहीं दी गई। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा भी राष्ट्रपति भवन में लगी हुई थी। अब इस प्रतिमा के स्थान पर राजाजी के नाम से पहचान रखने वाले सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाई गई है जिसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जब राजाजी गवर्नमेंट हाउस (जिसे अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है) पहुंचे तो उन्होंने अपने कमरे में रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी के चित्र लगाए। राजाजी के विचारों और कार्यों में भारतीय चेतना और समस्त भारतीयों, खासकर कमजोर वर्गों के साथ जुड़ाव साफ दिखाई देता है।

राष्ट्रपति भवन 'राष्ट्र का भवन' है। यह देश के नागरिकों का है। राष्ट्रपति भवन और शिमला, हैदराबाद एवं देहरादून स्थित अन्य राष्ट्रपति भवन उन सभी लोगों

राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजाजी उत्सव

- राष्ट्रपति ने राजाजी के जीवन और कार्यों पर आधारित फोटो और पुस्तक प्रदर्शनी का भ्रमण किया। राजाजी के जीवन पर एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई।
- राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आनंद लिया।

गुलामी की मानसिकता से मुक्ति

महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अशोक मंडप के पास स्थित भव्य सीढ़ी पर स्थापित सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा ने एडविन लुटियंस की प्रतिमा का स्थान लिया है। यह पहल औपनिवेशिक मानसिकता के निशानों को मिटाने और भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और शाश्वत परंपराओं को गर्व से अपनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की श्रृंखला का एक हिस्सा है।

सरकार की 'सेवा भावना' को दर्शाते हैं बदलाव

राजभवन लोकभवन बन गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ बन गया है। केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन में बदल गया है। औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया है। इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है। ये बदलाव महज प्रतीकात्मक नहीं हैं बल्कि सरकार की 'सेवा भावना' को दर्शाते हैं।

...जब राष्ट्रपति भवन परिसर में राजाजी ने शुरू की खेती

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के लोगों को अकाल और सूखे जैसी विपत्तियों का कई बार सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भी नागरिकों को खाद्य संकट से जूझना पड़ा। देशवासियों के प्रति करुणा और किसानों को प्रेरित करने के लिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजाजी ने राष्ट्रपति भवन परिसर में अनाज उगाने के लिए खेती शुरू की। उन्होंने स्वयं खेत जोतकर एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया। इतना ही नहीं, विधि, स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक और आर्थिक सुधार, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, तमिल और अंग्रेजी लेखन, कविता और संगीत, राजनीति और शासन में उनके योगदान ने इन क्षेत्रों को समृद्ध किया।

> *यह प्रयास है जो दिखाता है कि भारत उन लोगों को सम्मान देना चाहता है जिन्होंने देश का भविष्य बनाया। यह उपनिवेशवादी सोच के असर को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। राजाजी एक प्रखर विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और प्रशासक थे। उनका जीवन सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

के स्वागत के लिए खुले हैं, जो भारत के लोकतंत्र की परंपराओं और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पहले राष्ट्रपति भवन के गलियारों में भारत का शोषण करने वाले ब्रिटिश साम्राज्यवादी अधिकारियों की तस्वीरें लगी होती थीं। अब 'परम वीर दीर्घा' नामक गैलरी परम वीर चक्र विजेताओं के चित्रों से सुशोभित हैं। भारत की शास्त्रीय भाषाओं के ग्रंथों और पांडुलिपियों में संचित ज्ञान की महान परंपरा को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर की स्थापना की गई है।

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्ण ने 'राजाजी उत्सव' में कहा कि राजाजी उत्सव मना कर हमने औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति की दिशा में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। भारत औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त हो रहा है। यह कोई एक घटना नहीं है। यह शासन, कानून, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान के क्षेत्र में निरंतर चल रहा परिवर्तन है। ■

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर

राजस्थान को विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र को मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि जब राजस्थान विकसित होगा, तो यहां के हर परिवार का जीवन समृद्ध होगा। राज्य और नागरिकों के जीवन को समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर में करीब 17,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ...

अच्छी सड़क, आधुनिक रेल और हवाई सुविधा से सिर्फ सफर आसान नहीं होता बल्कि इससे पूरे इलाके की किस्मत बदलती है। जब गांव-गांव तक अच्छी सड़कें पहुंचती है तो किसान अपनी फसल सही दाम पर बेच पाते हैं। व्यापारी आसानी से अपना सामान बाहर भेज पाते हैं। राजस्थान के अजमेर से विकास कार्यों के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब पर्यटक आते हैं तो स्वाभाविक है होटल चलते हैं, ढाबे चलते हैं, कचौड़ी और दाल बाटी ज्यादा बिकती है। यहां राजस्थान के कारीगरों का बनाया सामान बिकता है, टैक्सी चलती है, गाइड को काम मिलता है। यानी एक पर्यटक कई परिवारों की रोजी-रोटी बन जाता है। इसी सोच के साथ सरकार, राजस्थान में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है।

सरकार ने नदियों को जोड़ने का जो अभियान शुरू किया है, उसका बहुत अधिक फायदा राजस्थान को मिलना तय है। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना हो या यमुना-राजस्थान लिंक प्रोजेक्ट, डबल इंजन सरकार ऐसी अनेक सिंचाई परियोजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी जिले के लिए पानी की अनेक परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। हमारा प्रयास है कि राजस्थान में भूजल का स्तर भी ऊपर उठे।

राजस्थान को पीएम मोदी ने दी विकास परियोजनाओं की कई सौगात

- राजस्थान के अजमेर में 16,680 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन।
- इन परियोजनाओं में शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़कें, सिंचाई, ऊर्जा और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहित प्रमुख सेक्टर शामिल।
- पीएम मोदी ने राजस्थान में सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को 21,800 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए।

> *जैसे-जैसे राजस्थान में कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे यहां निवेश के लिए भी अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इर्द-गिर्द उद्योगों के लिए एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है।* **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

भारत-कनाडा की साझेदारी

पूंजी और सामर्थ्य की संयुक्त आर्थिक शक्ति

भारत और कनाडा जीवंत लोकतंत्र हैं, विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह परिवर्तन मजबूत घरेलू मांग, युवा जनसंख्या, बड़े पैमाने पर निवेश, डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत और भारत के रिफॉर्म एक्सप्रेस से संभव हुआ है। पूंजी और सामर्थ्य की संयुक्त शक्ति को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 27 फरवरी से 2 मार्च तक की भारत की आधिकारिक यात्रा में दिया और विस्तार...

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद, कार्नी की यह पहली भारत यात्रा है तो वहीं 2018 के बाद कनाडा के किसी प्रधानमंत्री की भारत की यह पहली यात्रा भी रही। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए और कई घोषणाएं भी की गईं। दोनों देश के नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य में कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 79वीं वर्षगांठ मनाते हुए, कनाडा-भारत संबंधों के महत्व की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने उच्च-स्तरीय संवाद जारी रखने का स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि संयुक्त वक्तव्य में जिन पहल का उल्लेख है, वह भारत-कनाडा साझेदारी को और गहरा करेंगी। परस्पर विश्वास को मजबूत करेंगी। दोनों देशों और उनके लोगों के लिए ठोस, दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-कनाडा सीईओ फोरम को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी केवल नेशनल कैपिटल्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, हमें इसे राज्य और प्रांतों तक ले जाना होगा।

> *भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हम डायवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

प्रधानमंत्री का संयुक्त वक्तव्य देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

समझौते

- भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की संदर्भ शर्तें।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग पर भारत-कनाडा-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समझौता।
- परमाणु ऊर्जा विभाग व कनेडियन कैमेको के बीच यूरेनियम अयस्क सांद्रण की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक अनुबंध।
- ग्लोबलिंक रिसर्च इंटर्नशिप के लिए एआईसीटीई और कनाडा की मिटैक्स के बीच समझौता।
- महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग के लिए समझौता।
- नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर समझौता।
- सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता।

घोषणाएं

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य सेवा, कृषि व इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों/संस्थानों के बीच 24 समझौता।
- कनाडा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस में शामिल होगा। भारत-कनाडा संसदीय मैत्री समूह की स्थापना।
- भारत-कनाडा सीईओ फोरम का पुनर्गठन।
- भारत-कनाडा रक्षा संवाद की स्थापना।
- यूनिवर्सिटीज कनाडा द्वारा एक नई कनाडा-भारत संयुक्त प्रतिभा और नवाचार रणनीति का शुभारंभ।

भारत-फ्रांस सहयोग का नया अध्याय

रणनीतिक विश्वास से वैश्विक नेतृत्व तक

भारत और फ्रांस के बीच दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी ने हाल के वर्षों में नई ऊंचाई छुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्य, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के समर्थन और वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता ने दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार बनाया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की चौथी भारत यात्रा ने इस विश्वास एवं सहयोग को और मजबूत किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे भारत-फ्रांस संबंधों को मिलेगी नई दिशा और गति...

भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2047 में राजनयिक संबंधों के 100 वर्ष और रणनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा- सुरक्षा सहयोग का लंबा और मजबूत इतिहास रहा है। फ्रांस भारत के प्रमुख रक्षा साझेदारों में शामिल है। असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। हालिया दौरे में बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के साथ-साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। इमैनुएल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत यात्रा पर रहे और इस दौरान उन्होंने मुंबई और दिल्ली में आयोजित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया।

दुनिया के दो बड़े इनोवेशन हब्स (भारत और फ्रांस) एक

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

हेलीकॉप्टर और जेट इंजन के क्षेत्र में हुआ अहम समझौता

भारत और फ्रांस ने राफेल-मरीन लड़ाकू जेट विमानों की खरीद के अनुबंध की सराहना की। रक्षा विमानन, विशेष रूप से 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत लड़ाकू विमान और इसके इंजनों के निर्माण के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी। भारतीय बहु-भूमिका हेलीकॉप्टर (आईएमआरएच) के विकास के लिए सैफरान और एचएएल के बीच चल रही साझेदारी पर भी चर्चा हुई। भारत-फ्रांस ने लीप इंजन के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा के उद्घाटन, राफेल विमानों पर लगे एम-88 इंजनों के लिए एमआरओ सुविधा की स्थापना और भारत में हैमर मिसाइलों के उत्पादन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम का स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से एच125 फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। यह भारत में अपनी तरह का पहला निजी क्षेत्र हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र है। यह 'मेक इन इंडिया' के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस की ताकत को मिलाकर भारत के बढ़ते बाजार की जरूरतों को पूरा करेगी और तीसरे देशों को निर्यात करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पिनाका एमबीआरएल में फ्रांस की बढ़ती रुचि की सराहना की।

पीएम मोदी को दिया निमंत्रण

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2026 में फ्रांस की मेजबानी में होने वाले जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। भारत को शिखर सम्मेलन से पहले की चर्चाओं और तैयारियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। जहां मुख्य रूप से वैश्विक व्यापक आर्थिक असंतुलन से निपटने, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और एकजुटता के लिए एक नए प्रतिमान परिभाषित करने जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चाएं होंगी।

> *प्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रटीजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस रणनीतिक साझेदारी को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इसी विश्वास और साझा विजन के आधार पर, आज हम अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह साझेदारी केवल रणनीतिक नहीं है। आज के उथल-पुथल से भरे युग में यह वैश्विक स्थिरता और वैश्विक प्रगति की साझेदारी है।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

साथ आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते इनोवेशन के साथ-साथ ट्रस्ट का शेयर्ड वैल्यू का है। इसी सोच के साथ दोनों ने वर्ष 2026 को भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष भारत और फ्रांस में इनोवेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य सेवा, सतत विकास, सांस्कृतिक, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और अनुसंधान एवं शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में कई प्रभावशाली सहयोग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान निकायों और उद्योग के बीच मौजूदा सहयोग को समृद्ध करने के साथ ही नए अवसर सृजित करना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त बयान में कहा कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से एक दशक में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। 2014 में भारत में जहां सिर्फ चार यूनिकॉर्न थे, आज भारत में 120 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। इनकी टोटल वैल्यू 350 अरब डॉलर से अधिक है। आज दुनिया की करीब-करीब हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी भारत के स्टार्टअप, भारत के इनोवेशन से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के इस स्पीड और स्केल के साथ जब फ्रांस की ताकत जुड़ जाती है तो दुनिया के लिए नए रास्ते बनते हैं। दोनों देशों के बेस्ट माइंड एक साथ आए हैं। दोनों देश एक दूसरे के टैलेंट का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। फ्रांस ने 2030 तक 30 हजार भारतीय छात्रों का स्वागत करने का लक्ष्य रखा है। ये यंग एनर्जी और यंग माइंड्स के तालमेल का एक बेहतरीन प्रयास है।

रणनीति से नवाचार तक

भारत-इजरायल संबंधों का विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा भारत की विदेश नीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इस यात्रा ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी स्वतंत्र और संतुलित कूटनीति के तहत राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, इनोवेशन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिली और भारत-इजरायल संबंध रणनीतिक साझेदारी के एक नए युग में किया प्रवेश...

भारत सरकार ने भले ही वर्ष 1950 में इजरायल को औपचारिक मान्यता दी हो लेकिन दोनों के संबंध दो हजार साल से भी ज्यादा पुराने हैं। बुक ऑफ एस्टर में भारत का उल्लेख 'होदू' के रूप में मिलता है और प्राचीन समय में तालमुड में भारत के साथ व्यापार का विवरण भी दर्ज है। अब भारत-इजरायल संबंधों को पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वर्ष 2006 में, वहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वर्ष 2017 में और अब 25 एवं 26 फरवरी 2026 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को एक

> "पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा हित जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है।
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

दोनों देशों के बीच मुख्य घोषणाएं

- संबंधों को नए रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाना।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समिति (जेसीएम) को मंत्री स्तर पर उन्नत करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के नेतृत्व में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग की पहल।
- वित्तीय संवाद (फाइनेंशियल डायलॉग)।
- टेक-गेटवे पहल।
- कृषि अनुसंधान में 20 संयुक्त फेलोशिप।
- संयुक्त अनुसंधान के लिए दोनों पक्षों के योगदान में वृद्धि।
- अगले 5 वर्षों में 50,000 भारतीय श्रमिकों तक का कोटा।
- भारत-इजरायल शैक्षणिक सहयोग मंच।
- भारत-इजरायल संसदीय मैत्री समूह।

सहमति और समझौते

- भू-सर्वेक्षण और खोज के क्षेत्र में सहयोग।
- राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास हेतु सहयोग।
- वर्ष 2026-2029 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
- यूपीआई के कार्यान्वयन पर एनपीसीआई इंटरनेशनल और एमएएसएवी के बीच समझौता।
- कृषि के लिए भारत-इजरायल नवाचार केंद्र (आईआईएनसीए) की स्थापना हेतु समझौता।
- होराइजन स्कैनिंग के क्षेत्र में सहयोग।
- मत्स्य पालन और जलीय कृषि।
- इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी और इजरायल सिक्योरिटी अथॉरिटी के बीच सहयोग।
- वाणिज्य और सेवा क्षेत्र में लेबर मोबिलिटी के कार्यान्वयन पर प्रोटोकॉल।
- विनिर्माण क्षेत्र में लेबर मोबिलिटी के कार्यान्वयन पर प्रोटोकॉल।
- रेस्तरां क्षेत्र में लेबर मोबिलिटी के कार्यान्वयन पर प्रोटोकॉल।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने में सहयोग।
- इजरायली इंस्टीट्यूट ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के बीच सहयोग।
- चौथे भारत-इजरायल सीईओ फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत।
- नालंदा विश्वविद्यालय और यरुशलम के हिब्रू विश्वविद्यालय (एचयूजेआई) के बीच समझौता।
- भारत में भारत-इजरायल साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में सहयोग पर समझौता।

नए शिखर तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौ वर्ष पहले इजरायल की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने थे।

यात्रा के दौरान इजरायल की 'नेसेट' को संबोधित करने वाले प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले पीएम भी बने। प्रधानमंत्री मोदी, भारत के सम्मान में नेसेट को भारतीय रंगों से अलौकिक किया गया था। पीएम मोदी की एक बात ने नेसेट में उनके संबोधन को खास बना दिया, जब उन्होंने कहा कि मेरा जन्म उसी दिन यानी 17 सितंबर, 1950 को हुआ था, जिस दिन भारत ने इजरायल को औपचारिक मान्यता दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि भारत आपके दर्द को महसूस करता है, इसलिए आपके दुख में शामिल है। भारत इस समय और आगे भी इजरायल के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा है।

कोई भी उद्देश्य निर्दोष नागरिकों की हत्या को उचित नहीं ठहरा सकता। आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। भारत ने भी लंबे अर्से तक आतंकवाद की पीड़ा झेली है। 26/11 के मुंबई हमले भी याद हैं, जिनमें बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन हमलों में मारे गए लोगों में इजरायली नागरिक भी शामिल थे। इजरायल की तरह ही, आतंकवाद के

तकनीकी प्रदर्शनी का दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में इजरायल के इनोवेशन को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में कृषि-तकनीक, जल-तकनीक, जलवायु-तकनीक, स्वास्थ्य-जैव-तकनीक, स्मार्ट मोबिलिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और क्वांटम प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता रखने वाली अग्रणी कंपनियों और अनुसंधान संस्थाओं को शामिल किया गया था।

"स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल" से सम्मानित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'स्पीकर ऑफ द नेसेट' से सम्मानित किया गया। इजरायल की संसद में नेसेट ने भारत-इजरायल रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को देखते हुए यह सम्मान दिया। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। यह नेसेट का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासी और भारत-इजरायल मित्रता को समर्पित किया।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

दोनों देशों के संयुक्त बयान में इन विषयों पर रहा फोकस

प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बैठक के बाद जब संयुक्त बयान जारी किया गया तब साझा बातचीत के जिन विषयों पर फोकस रहा उनमें प्रमुख हैं शांति, नवाचार और खुशहाली के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी, भविष्य में साथ, रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, साइबर सुरक्षा, व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी, खेती, पानी और पर्यावरण की सुरक्षा, आतंक का मुकाबला, शांति को बढ़ावा देना, संसदीय सहयोग, लोगों के बीच सहयोग, स्वास्थ्य और शिक्षा-भविष्य को सुरक्षित करना।

प्रति भारत की नीति भी बिना किसी दोहरे मानदंड के, निरंतर और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित गाजा शांति पहल, एक रास्ता दिखाती है। इस पहल के प्रति भारत ने दृढ़ समर्थन व्यक्त किया है। विश्वास है कि यह पहल फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान सहित क्षेत्र के सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का आश्वासन देती है।

द्विपक्षीय व्यापार में कई गुना की वृद्धि

हाल के वर्षों में भारत-इजरायल के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है। यही कारण है कि दोनों देशों की टीम एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में कड़ी मेहनत कर रही है। भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारा तथा भारत, इजरायल, यूएई और अमेरिका के बीच I2U2 फ्रेमवर्क सहित विभिन्न ढांचों में भी निकटता से काम करेगा। सटीक सिंचाई और जल प्रबंधन में इजरायल की विशेषज्ञता ने भारत की कृषि प्रथाओं को बदल दिया है। भारत में 43 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे 5 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया है। अब इन केंद्रों की संख्या 100 तक बढ़ाने का लक्ष्य है ताकि लाखों किसानों और मछुआरों को लाभ मिल सके। ■

PMO India
@PMOIndia

पिछले एक दशक में infrastructure पर हमारा बहुत focus रहा है।

हमने सोच-समझकर ये फैसला किया कि भारत का विकास... Highways, Railways, Ports, Digital Network, Power Systems जैसे ठोस Assets को तैयार करके ही होगा।

ये आने वाले कई दशकों तक Productivity पैदा करेंगे।

इसी वजह से Public Capital Expenditure लगातार बढ़ाया जा रहा है: PM @narendramodi

Rajnath Singh
@rajnathsingh

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कच्चे जूट की MSP को ढाई गुना बढ़ाकर ₹5,925 प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय जूट किसानों की आमदनी में वृद्धि करेगा और किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा।

Amit Shah
@AmitShah

अतिक्रमण से, घुसपैठ से होने वाला डेमोग्राफी बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल, तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है। मोदी सरकार इसका स्थायी समाधान करेगी।

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

Union Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Shri @narendramodi Ji, has approved the Minimum Support Price (MSP) for Raw Jute for the Marketing Season 2026-27.

Ashwini Vaishnaw
@AshwiniVaishnaw

Global AI leaders uniting at the AI Impact Summit, to discuss and bring out AI's real impact on society.

Shaping AI for humanity: responsibly, inclusively, and at scale.

Kiren Rijiju
@KirenRijiju

हमारी कार्य-संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए, उसे पूरा करने के लिए दिन-रात एक कर दिया जाए।

इसलिए, अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती, भटकती नहीं हैं।

नमो भारत या मेट्रो सेवा, दोनों का शिलान्यास करने का अवसर आप सब ने मुझे दिया था, और आज मुझे ही इनके लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है: माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी

दिल्ली से मेरठ अब 55 मिनट में

82 किमी लंबे नमो भारत कॉरिडोर पर ट्रेनों ने पकड़ी रफ्तार

सर्वाइकल कैंसर से जंग का आगाज

प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान

1.20 करोड़ बेटियों को लगेगा टीका

कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा देश : मोदी

पीएम सूर्य घर से 30 लाख घर हुए रोशन, ऊर्जा क्रांति की ओर बढ़ता भारत

भारत के पास अद्भुत क्षमताएं...एआई के इस्तेमाल पर दुनिया को दिखाई दिशा : मोदी

प्रधानमंत्री ने साणंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया, कहा

भारत अब सक्षम है, प्रतिस्पर्धी और प्रतिबद्ध है

भारत और इस्राइल विशेष रणनीतिक साझेदार, मुक्त व्यापार समझौता जल्द

कनेक्टिविटी में आएगी क्रांति, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे और लोगों का जीवन बदलेगा

नेतन्याहू संग टेक, मिडिल ईस्ट के ताजा हालात पर चर्चा की: मोदी

शहीद दिवस : 23 मार्च

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कृतज्ञ राष्ट्र का नमन

‘राष्ट्र हित सर्वोपरि’ के प्रेरणास्रोत

मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु, और सुखदेव ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने इन तीन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दे दी थी। इन वीरों को नमन करने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने शौर्य और ओजस्वी विचारों से युवाओं में देशभक्ति का संचार कर, राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता आंदोलन की अलख जगाने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान युगों-युगों तक देशवासियों को ‘राष्ट्र हित सर्वोपरि’ की देता रहेगा प्रेरणा...

“देश भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सर्वोच्च बलिदान पर उनको नमन कर रहा है। स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनका निडर प्रयास हम सभी को प्रेरित करता है। **–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 16-31 मार्च, 2026

आरएनआई DELHIN/2020/78812 (प्रकाशन तिथि- 6 मार्च 2026, कुल पृष्ठ-52)

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक
कंचन प्रसाद
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित